>

Title: Further discussion regarding special economic development package for the desert regions of the Country moved by Shri Harish Chaudhury on the 26th August, 2011.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, पिछली दफा मैंने राजस्थान में क्या स्थिति है, उसके संदर्भ में आपके माध्यम से सदन और सदन के माध्यम से देश को अवगत कराने की कोशिश की थी।

महोदय, आज मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो समस्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है? हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। रेगिस्तान में पानी की बहुत किल्लत है और जो पानी है, वह भी पीने योग्य नहीं है। मैंने पहले भी यह बताया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के 90 प्रतिशत गांवों में पेयजल पीने योग्य नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के लिए नहरों के माध्यम से पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है, उसके लिए केन्द्र सरकार प्राथमिकता से सहयोग करे। हमारा पानी के संरक्षण का पारम्परिक तरीका है। आज पूरी दुनिया इज़राइली मॉडल की चर्चा करती है, लेकिन रेगिस्तान के अंदर टाके के रूप में सौ और दो सौ एमएम की बारिश से पानी का संचय किया जाता है।

सभापति महोदय : ड्रिप सिस्टम।

श्री हरीश चौधरी : नहीं, टाका एक पक्का पोंड है, उस पोंड का कैचमेंट एरिया भी पक्का किया जाता है। पारम्परिक तौर पर वह गाय के गोबर से लीपा जाता था, आजकल वह सीमेंट से किया जाता है। आने वाले समय में जब वैकल्पिक स्रोत बन जाएंगे, चाहे वह स्थानीय हों या पेयजल के लिए बड़ी स्कीम के माध्यम से जो सोच रहे हैं, लेकिन इन टाकों को कहीं हम भूल न जाएं। आज वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़े पैमाने पर हम इसकी एडवोकेसी करते हैं। इसके बारे में प्रचार-प्रसार करते हैं। लेकिन जो समाज पारम्परिक तौर पर इसको एडॉप्ट कर चुका है और आने वाले समय में वे इसको छोड़ न दे और ऐसा कई क्षेत्रों में हो चुका है। रेगिस्तानी इलाके के नहरी क्षेत्र में आज टाके नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को एक बात और बताना चाहता हूं कि इन टाकों में व्यक्तिगत लाभार्थी के टाकें शत-प्रतिशत रेगिस्तान में सफल हो रहे हैं और जो कम्यूनिटी बेस्ड टाकें हैं, वे 90 प्रतिशत तक असफल हैं। आज हम लोग कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन का धरातल पर क्या हश्र हो रहा है और क्या हालत हो रही है, यह भी हम लोगों को देखना चाहिए। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र में चार मेजर स्कीम्स चल रही हैं, उसमें केन्द्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। पांचवी स्कीम हमारे यहां आईजीएनपीसी गढवा की है। उस डेज़र्ट नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता है, ऐसा वहां प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल पाइप निकालने के लिए हम लोगों की जो मांग है, उस पर गौर करें। गढवा का इलाका पाकिस्तानी बार्डर से बिलकुल सटा हुआ रेगिस्तानी इलाका है और उसके लिए पेयजल योजना के संदर्भ में यह किया जाए।

सभापति महोदय, हम लोगों के रेगिस्तानी इलाके में आगजनी की समस्या बहुत बड़ी है। यहां बैठकर आगजनी की घटना को हम बहुत छोटी मानते हैं। हम लोगों के यहां पक्के आवास बहुत कम हैं और अधिकतर कच्चे झोपड़ें हैं। जब उस झोपड़े में एक दफा आग लग जाती है तो 15 से 20 मिनट में वह पूरा झोपड़ा खत्म हो जाता है, वह आवास पूरा खत्म हो जाता है। उसके अन्दर जितने भी उस किसान के या उस गांव में रहने वाले व्यक्ति की जो भी सामग्री रहती है, वह सब खत्म हो जाती है। इसके साथ-साथ उनके पशु भी ज्यादातर उस आगज़नी में खत्म हो जाते हैं। सिर्फ़ पशु ही नहीं, कई बार उसके घर में कोई बुज़ुर्ग या बच्चे रह जाते हैं तो वे भी मर जाते हैं। तीन दिसम्बर को मेरे लोकसभा क्षेत्र के बायतू चिमंजी ग्राम पंचायत के अंदर आगज़नी की घटना हुई। उस आगज़नी में दो छोटे-छोटे मासूम बच्चे, सात वर्षीय बाली, और चार वर्षीय वीरा की मृत्यु हो गयी। यह केवल साल में एक-दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ बाड़मेर जिले के अंदर देखें तो वर्ष 2008-09 में लगभग 625 घटनाएं, वर्ष 2009-10 में लगभग 650, और वर्ष 2010-11 के अंदर 635 घटनाएं हैं। इस तरह एक जिले के अंदर ही आगजनी से इतनी ढानियां जल जाती हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ढानियों का और कच्चे मकानों का जो कम्पेनशेसन देते हैं, उसे बढ़ाएं। पहले वह दस हजार रुपए दिया जाता था। अभी पिछले दिनों ही जनवरी के अंदर उसे दस हजार रुपए से बढ़ाकर पन्द्रह हजार रुपए किए थे। वह पन्द्रह हजार रुपए बहुत कम है। आज पन्द्रह हजार रुपए की क्या क़ीमत है, वह भी देखनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि उस कम्पेनशेसन को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपए कर देना चाहिए। केन्द्र सरकार ने आगजनी के कारण होने वाले मृत्यु के लिए एक लाख से बढ़ाकर जो डेढ़ लाख रुपए किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह हम लोगों की बड़े समय से मांग थी। आगज़नी के कारण जिनकी ढानियां जल जाती हैं, उसको तुरन्त ही बीपीएल परिवार में सम्मिलित किया जाए और बीपीएल के परिवारों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए और उन लोगों को इन्दिरा आवास भी तुरन्त मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, चर्चा के अन्दर यह बहुत छोटी सी बात नजर आती है, पर एक जिले के अन्दर इस तरह की घटनाओं से 625-650 परिवार की एक तरह से जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। वे अपने जीवन को वापस कैसे शुरू करें, इसकी कितनी पीड़ा होती है, यह उन लोगों को ही पता है। मेरा केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि इस पर प्राथमिकता पूर्वक विचार करें।

महोदय, आज रेगिस्तानी इलाके में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों की शिक्षा के मामले में रेगिस्तानी इलाके में शिक्षा से तुलना करें तो कोई भी स्थिति अच्छी नहीं है। इससे भी दुर्भागयपूर्ण पहलू यह है कि रेगिस्तानी इलाके में शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। आज केन्द्र सरकार शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि योजनाएं बनाती है, पर मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के अन्दर वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 के अन्दर डेढ़ प्रतिशत साक्षरता दर कम हुई है। महिलाओं की शिक्षा के बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में महिला साक्षरता दर 2.45 प्रतिशत कम हुई है। आज हम लोग साक्षरता पर बहुत चर्चा करते हैं और इसका प्रचार-प्रसार करते हैं, पर धरातल पर जब पिछड़े हुए इलाके की स्थिति देखते हैं तो यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि आज हम शिक्षा नीति के अंतर्गत नामांकन के लिए अंधे होकर दौड़ रहे हैं। अगर आज ग्रामीण परिवेश के किसी विद्यार्थी को गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोजगार सृजन के लिए वह शिक्षा किस काम आएगी? इससे आने वाले समय में देश के लिए एक अलग समस्या हो जाएगी। आज जो शिक्षित नवयुवक हैं, अगर इनके रोजगार को हम इंश्योर नहीं कर रहे हैं तो उनकी समस्या अलग हो जाएगी। आज जो नक्सलवाद की समस्या है जिसकी हम पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा कर रहे हैं, अगर हम अपने युवकों को आधी-अधूरी शिक्षा देंगे तो वह बहुत खतरनाक है।

महोदय, हम लोगों ने अपनी शिक्षा नीति के अंतर्गत आठवीं कक्षा तक परीक्षा को समाप्त कर दिया है। आज हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर अगर पढ़ने के लिए कोई एकमात्र राइडर है तो वह परीक्षा है। घर वाले कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करो, परीक्षा आ गयी। इसके लिए बच्चे परीक्षा में अच्छा करने के लिए ज्यादा पढ़ाई करते हैं और शिक्षक भी इसके लिए कोशिश करते हैं। परीक्षा एक राइडर है जिसके कारण ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति के अन्दर आठवीं कक्षा तक वह राइडर भी हटा दिया गया। आज ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की क्या स्थिति है, वह बहुत अलग है। आज रेगिस्तानी इलाकों में कोई शिक्षक जाना नहीं चाहता है। उसकी पोस्टिंग की अंतिम प्राथमिकता रेगिस्तानी इलाके की होती है। अगर पोस्टिंग हो भी जाती है तो उस स्कूल में जाकर पढ़ाने की उसकी रूचि बहुत कम होती है। अगर वहां हम परीक्षा को हटा देते हैं तो क्या हम रेगिस्तानी इलाके के उन युवकों और विद्यार्थियों को आने वाले समय में कॉरपोरेट और पब्लिक स्कूल से कम्पीट करने के लिए सक्षम बना रहे हैं? यह भी हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और मॉडल स्कूलों के लिए केन्द्र सरकार जो प्रावधान रखती है, उसके तहत रेगिस्तानी इलाके में एक जिले में एक ही नवोदय विद्यालय होता है। रेगिस्तानी इलाके के लिए एक ही जगह उसकी संख्या बढ़ाई जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय, मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर इस वर्ष दो केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में रेगिस्तानी इलाके के अंदर केन्द्रीय विद्यालयों की भी ज्यादा से ज्यादा संख्या हो। मॉडल स्कूल, जो प्रत्येक ब्लॉक पर एक है, रेगिस्तानी इलाके के अंदर बहुत लम्बी दूरी से बच्चा पढ़ने के लिए आता है। वहां एक-एक गांव 80-80 किलोमीटर का है। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर रामगढ़ ग्राम पंचायत हैं, वह एक ग्राम पंचायत 80 किलोमीटर है। कई राज्य होंगे, जो 80 किलोमीटर के अंदर हैं और एक ग्राम पंचायत 80 किलोमीटर के अंदर है। आने वाले के समय के अंदर अच्छी गुणवंता की शिक्षा रेगिस्तानी इलाके के ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी को कैसे मिले, यह हम लोगों के सामने चुनौती है। वह स्कील डेवेलपमेंट भी होना चाहिए। अगर दसवीं, 12वीं पढ़ा कर हम लोग उन बच्चों का रोजगार का सृजन नहीं कर सकते और दो हिन्दुस्तान की चर्चा की हम बात करते हैं, दूसरा हिन्दुस्तान क्या है, वह रेगिस्तान में आकर देखिए। आज जो सब चीजों से वंचित है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा आदि चीजों से भी वह वंचित है।

बिजली के संदर्भ में मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंदर सबसे ज्यादा अगर कार्य हुआ है तो वह रेगिस्तानी इलाके के अंदर और विशेषकर बाड़मेर जिले के अंदर हुआ है। दो सौ करोड़ रुपए राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंदर बाड़मेर जिले में खर्च हुआ है, परन्तु सिर्फ पच्चास प्रतिशत बीपीएल परिवार हैं, उन दो सौ करोड़ के अंदर बिजली से जुड़ पाए हैं, पच्चास प्रतिशत आज भी नहीं जुड़ पाए। बाकी दूसरी जगह गांव साथ में बसा है, जितने भी लोग वहां रहते हैं, वे एक गांव में रहते हैं। हम लोगों के रेगिस्तानी इलाके के अंदर सब खेतों में रहते हैं। खेतों में रहने के कारण बिजली को उन तक पहुंचाने का जो खर्चा है, वह बहुत ज्यादा हो जाता है।

इसलिए आपसे यही निवेदन है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंदर, या तो इसी के अंदर हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए या अन्य दूसरे चरण के अंदर ऐसी कोई योजना स्वीकृत की जाए, जिससे रेगिस्तानी इलाके के अंदर रहने वाले ग्रामीण लोगों को भी बिजली मिल सके। बड़े-बड़े कार्पोरेट्स के पास जेनरेटर एवं इनवर्टर्स हैं, परन्तु उस गांव के गरीब के लिए पांच-छ: घंटे जो बिजली आती है, उनकी जो मिनिमम जरूरते हैं, वह उन्हें पांच-छ: घंटे में पूरी कर सकता है। वह रोशनी भी उन लोगों को दिखाई, यह हम सब लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। सड़क के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत काम हुआ है। रेगिस्तानी इलाके के अंदर ढाई सौ की संख्या के अंदर हम लोगों ने पैमाना रखा है। पहले राजस्व गांव के समय पैमाना था. अब उस राजस्व गांव की जगह हैबिटेशन के कलस्टर का पैमाना रखा गया है। वह हैबिटेशन का कलस्टर भी उस राजस्व गांव के अंदर इतना नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से रेगिस्तानी इलाके को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा हो। रेलवे क्रॉसिंग के भी हम लोगों ने जो पैमाने रखे हैं, 40-40 किलोमीटर तक रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। वह गरीब आदमी, जिसके पास संसाधन नहीं हैं, रेलवे क्रॉसिंग न होने के कारण 40-50 किलोमीटर दूर उसे किसी कस्बे में या कहीं अन्य जगह किसी काम के लिए जाना पड़ता है तो वह कैसे जाए। उसके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, इसका फैसला सदन ही करे।

आज नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल रेल डेवेलपमेंट फंड के नाम पर पर्वतीय क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं, परन्तु इसी प्रकार की योजनाएं रेगिस्तानी इलाके के अंदर भी होनी चाहिए। अगर रेलवे नेटवर्क रेगिस्तानी इलाके के अंदर बढ़ेगा तो हम लोगों के यहां भी उससे फायदा होगा। जैसलमेर, बाड़मेर, कांडला, जैसलमेर आज बीकानेर से जुड़ चुका है, .ये पूरा रेगिस्तानी इलाका अगर समुन्द्र तट से जुड़ेगा तो वहां इकोनोमी एक्टीविटीज़ बहुत होंगी और हम लोगों को रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर भी मिलेंगे।...(<u>व्यवधान</u>) स्टॉर्ट प्रश्न 262, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 का जो था, उसके अंदर केन्द्र सरकार ने बताया कि लगभग तीस स्टेट और युनियन टैरेटरी के अंदर एपीएल परिवार को 15 किलो पर-फैमिली पर-मंथ अनाज दिया जाता है और जो नॉर्थ-ईस्ट स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड है, इनके अंदर, आपके खुद के स्टेट के अंदर 35 किलो दिया जाता है। रेगिस्तान के अंदर अनाज की बहुत ज्यादा कमी है। वहां के लोग बहुत गरीब हैं, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि 35 किलो हम लोगों को भी मिले। आज आप खुद भी राजस्थानी रंग में रंगे हुए हो। आपकी पगड़ी भी रेगिस्तानी है।

आज हमारी खुशकिस्मती है कि हैल्थ मिनिस्टर यहां मौजूद हैं। हैल्थ के अंदर रेगिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री जी, जरा सुन लें, माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। मंत्री जी सुन रहे हैं, बोलिये।

श्री हरीश चौधरी : मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोगों के वहां रेगिस्तान के अन्दर ज्यादातर बीमारियां मलेरिया की हैं, पथरी की हैं, सांस की हैं और आंखों की हैं। मलेरिया में 1994 के अन्दर भी सैंकड़ों मौतें रेगिस्तानी इलाकों के अन्दर हुई। आजकल मलेरिया के लिए हम लोग जो फंड दे रहे हैं, उसका यूटीलाइजेशन पूरे रेगिस्तानी इलाके में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी तरफ भी देखें। आज जो भी हम लोगों ने स्वास्थ्य के अन्दर सुविधाओं के पैमाने बना रखे हैं, वे जनसंख्या के आधार पर बना रखे हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर ही वे पैमाने रहे...(<u>व्यवधान</u>) मैं इसका इन्तजार कर रहा हूं कि जब पहाड़ जैसा हम लोगों का रेगिस्तान भी बने। गुलाम नबी जी की कब उन रेगिस्तानी इलाकों के ऊपर भी नज़रे इनायत हो। अगर हम लोगों की पोपुलेशन के हिसाब से जो पैमाने बने हुए हैं, जनसंख्या के आधार पर अगर वही पैमाने रहे तो रेगिस्तानी इलाके के अन्दर हम लोगों की जो मूलभूत चिकित्सा की सुविधा है, वे हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज मेरे खुद के बाड़मेर जिले के अन्दर लगभग 2465 राजस्व गांव हैं और अगर सब सैण्टर्स भी अगर हम उनमें देखें तो अभी तक 550 सब सैण्टर्स भी नहीं हैं। बहुत ज्यादा ऐसे राजस्व गांव हैं, जिनके अन्दर सब सैण्टर्स की भी हम लोगों को सुविधा नहीं है। पी.एच.सी. हैं, सी.एच.सी. हैं, वे भी जनसंख्या के आधार पर जो पैमाने बनाए हुए हैं...(<u>व्यवधान</u>)

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप उनकी बात सुनें।

श्री हरीश चौधरी : थोड़ा सुन लें, सर। मंत्री जी, कभी कभार तो हमारा, रेगिस्तानी इलाके वालों का नम्बर आता है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि अपनी

आवाज बुलन्दी से हम उठा सकें। वह ताकत हम लोगों के पास नहीं है कि संसाधन से हम लोग अपनी ताकत का इजहार कर सकें। कुछ ताकत दिखाकर हम लोगों को न्याय दिला सकें।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): यहां राजस्थान की बात हो रही है और कोस्टल एरिया वाले मंत्री जी को घेरे हुए हैं।...(व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी : यही स्थिति रेगिस्तान की है, वह सबसे अन्तिम प्राथमिकता में आज देश के निर्णय के संदर्भ में है। पी.एच.सी., सी.एच.सी. जैसी चीजें भी हमारे राजस्थान के अन्दर अगर जनसंख्या के आधार पर रहेंगी तो हमें न्याय नहीं मिल सकता। आज लोग तड़प कर वहां संसाधन के बिना...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: बेचारों को बाद में इसमें तो मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने ऐसे एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़, हिली एरियाज़, जिसमें इनका रेगिस्तानी इलाका भी है, चाहे वह कच्छ का एरिया हो या रेगिस्तान में बाड़मेर का, जैसलमेर का एरिया हो, ये एरियाज़ हमने उसमें रखे हैं और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सारी चीजें, चाहे वे सब सैण्टर्स हों या प्राइमरी हैल्थ सैण्टर्स हों, ये कई चीजें हैं, वे आबादी के हिसाब से हैं तो करीब 265 डिस्ट्रिक्ट्स हमने चुन लिए हैं, जहां आबादी के हिसाब से नहीं, बल्कि उनकी बैकवर्डनैस के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से हम प्राथमिकता देंगे।

सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी : धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने जब यह मंत्रालय संभाला था, उस समय हम लोगों को यह आशा थी कि हम लोगों को इस बार जरूर न्याय मिलेगा और उस आशा के अनुरूप ही आपका काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से प्लानिंग कमीशन को भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका भी जो पैमाना है, पिछड़े हुए जिलों में, पिछड़े हुए इलाकों के पैमाने में इसे सम्मिलित करना चाहिए। पाले और शीतलहर के सन्दर्भ में भी एक ही समस्या है। मंत्री महोदय, हम लोगों के यहां अगर थोड़ी बहुत भी सर्दी ज्यादा पड़ जाती है, पाला पड़ जाता है तो जो फसलें हम लोगों के वहां होती हैं और वह भी अगर शीतलहर है तो दोनों की दोनों कैलेमिटीज़ को रिलीफ फंड के अन्दर सम्मिलित नहीं किया गया। इसके कारण जब कभी भी किसान को इससे नुकसान होता है तो उसकी भरपाई नहीं होती है। मुझे आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अन्दर गृह मंत्रालय हमारे अनुकूल फैसला लेगा। पाले और शीतलहर को सी.आर.एफ. के अन्दर सम्मिलित होने के लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने एक जी.ओएम. बनाया और मैं पूरे जी.ओएम. को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे अनुकूल वहां से सिफारिश भेजी है। आने वाले समय के अन्दर रेगिस्तानी इलाके के किसान को भी सी.आर.एफ. में पाले और शीतलहर को सम्मिलित होने से जो राहत पहुंचेगी, उसका आप आकलन नहीं कर सकते। वहां बहुत गरीब लोग हैं, वे उधार पैसा लाकर वहां अपनी खेती में लगाते हैं। मैं राजस्थान सरकार को भी इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लाख का किसानों के कर्ज पर एक प्रतिशत भी ब्याज राजस्थान सरकार ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका दें, समय काफी हो गया है।

श्री हरीश चौधरी : पाला और शीतलहर के अलावा भी कई ऐसी समस्यायें हैं। अरंडी की फसल हमारे यहां है। अरंडी की बुआई हम लोग जुलाई-अगस्त में करते हैं, उसकी कटाई मार्च में होती है। खरीफ के अंदर उसकी गिरदावरी हो जाती है, तो मार्च के अंदर, रबी के अंदर उसकी हम लोग पैदाइश लेते हैं, तो उसमें उनको अगर नुकसान भी हो जाता है, तो उसका फायदा हम लोगों को नहीं मिलता है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और बात फसल बीमा के संदर्भ में कहना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस कोई व्यक्ति कराता है, उसे सब प्रकार की पॉलिसीज लेने का अधिकार है तो फिर किसानों पर यह बाध्यता क्यों? अगर किसान चाहे तो वह मौसम आधारित पर ले और किसान चाहे तो वह क्रॉप कटिंग के आधार पर ले, किसान को कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो हम लोग दे दें। आज इस देश के अंदर किसान की आवाज लगभग समाप्त होती जा रही है। आज मजदूर की आवाज समाप्त होती जा रही है। फैसले लेते समय प्राथमिकता से हम उस किसान को कैसे जिन्दा रखें, उस मजदूर को कैसे जिन्दा रखें, यह हम लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। कम से कम फसल बीमा के संदर्भ हम लोग ऐसा करें।

मैं अन्तिम दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी हब है। आज भारत का 20 से 25 प्रतिशत क्रूड ऑयल सिर्फ बाड़मेर के अंदर हो रहा है। आने वाले समय के अंदर जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, उसके अंदर अगर वहां के लोगों को, तभी हम लोगों को फायदा मिलेगा, इसके लिए रिफाइनरी हम लोगों के वहां मिलनी चाहिए। इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं है, हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि इकोनॉमिक वॉयबिलिटी नहीं है, पर केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी जहां-कहीं निर्णय हुए हैं, चाहे पानीपत में हुआ है, चाहे भटिंडा के अंदर हुआ है, कोई इकोनॉमिक वॉयबिलिटी का जरिया निकाला है। मुझे आने वाले समय में केंद्र सरकार से पूरी आशा है कि रिफाइनरी के संदर्भ में जो इकोनॉमिक वॉयबिलिटी का गैप है, उसे केंद्र सरकार जरूर करेगी।

इसके अलावा वहां गैस का बहुत भण्डार है, कोयले का बहुत भण्डार है, बहुत विंड पावर है, सोलर का है, कोल बेस्ड मीथेन का है, आने वाले समय में एनर्जी के रूप में सबसे ज्यादा हम लोगों को जो स्रोत मिलेगा, वह शैल गैस है, उसका भण्डार भी रेगिस्तान के अंदर बहुत है।

महोदय, रेगिस्तान इतना कुछ देश को दे रहा है, बहुत छोटी सी चीज हम लोग मांग रहे हैं, जिससे हम जिन्दा रह सकें, जिससे पूरी दुनिया जहां विकसित हो रही है, उस विकास के अंदर थोड़ा सा एक कदम हम लोग भी चल सकें, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं।

हम लोगों के ऊपर जुल्म जरूर होता है, आज थार एक्सप्रेस को बाड़मेर में नहीं रोका जाता है, थार एक्सप्रेस को 500 किलोमीटर के बाद रोका जाता है। उसका कारण यह बताया जाता है कि हैबिटेशंस बहुत कम हैं, कोई भी मूवमेंट होगा, इन्टेलीजेंस एजेंसीज बताती हैं, उसे हम लोग चैक नहीं कर सकते। जो भी हम लोगों को नुकसान हो रहा है, वह नुकसान तो हो ही रहा है। नेशनल हाइवे नंबर 15 से उस तरफ हमारे प्राइवेट्री एरिया घोषित कर सकता है, कोई भी वहां नहीं जा सकता है।

सभापति महोदय : अपनी बात समाप्त करिए।

श्री हरीश चौधरी : जम्मू-कश्मीर में जा सकते हैं, पंजाब में जा सकते हैं, लेकिन जो रेगिस्तानी इलाका है, बाड़मेर में नहीं जा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं उन गरीब लोगों के लिए कहना चाहता हूं।

आखिरी में, एक बात कहकर मैं कंक्ल्यूड करना चाहता हूं, बहुत दुश्वार है जीवन, कोई देखे वहां रहकर, सितम जैसी वहां पर जिंदगी, देखे कोई सहकर, यही है हक, यही है फर्ज, यही है प्रार्थना मेरी, पहाड़ी क्षेत्र की तरह से रेगिस्तान भी महके।

MR. CHAIRMAN : Resolution moved:

"This House expresses its deep concern over the backwardness prevailing in the desert regions of the Country and urges upon the Government to prepare and implement a special economic package for:-

(i) overall development of desert regions on the lines of the economic pacheage provided to the north-eartern States to mitigate the problems being faced by the people living in desert regions; and

(ii) enabling the people of these regions to achieve a level of socio-economic development at par with the people living in other parts of the country."

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, लोक सभा के इस चैनल पर हिंदुस्तान के गांव के गरीब, किसान लोग भी जिनके घर में टीवी है, वह इसकी कार्यवाही को सुनते हैं, देखते हैं और इसमें दिलचस्पी लेते हैं। उनके मन और पेट की जो भूख है, इन दोनों भूख को शांत करने के लिए इस लोक सभा में कितनी बहस होती है और सरकार उसके प्रति कितनी सजग है, सहानुभूति रखती है, यह भी इस देश के लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इसलिए इस लोक सभा चैनल को जिन्होंने चलाया था, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भारत के गांव, गरीब, किसानों को भी लोक सभा का प्रत्यक्ष दर्शन हो पा रहा है। अभी हमारे साथी हरीश जी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के दुख-दर्द के बारे में बता रहे थे। मैं उतना तो नहीं घूमा हूं, लेकिन कभी किसी जमाने में हमारे नेता चौधरी देवीलाल जी थे, उनके साथ, उनके नेतृत्व में वहां के हमारे तीन नेता थे, माननीय कुंभाराम आर्य जी और दौलतराम सारंन जी, लालचंद डूडी जी, हम चौधरी देवीलाल जी के साथ नीमका थाना से निकलते थे। उनके साथ मैंने सीकर, चुरू, जालौर, बाड़मेर, पोखरन, बीकानेर की यात्रा की है। उनके साथ रात्री विश्राम भी किया है। एक बार चौधरी देवी लाल जी और मैं पोखरन जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुमने ढ़ाणी देखा है। मैंने कहा कि मेरे यहां धानी होती ही नहीं तो कहां से देखेंगे? उन्होंने कहा कि चल तुझे ढ़ाणी दिखाता हूं। सड़के के किनारे फूस का बड़ा-बड़ा छप्पर का मकान था। आज कल दिल्ली में एक ही कमरे के साथ डाइनिंग हाल एवं अन्य सभी कमरे बनें रहते हैं, उसी तरह का कमरा था। देवी लाल जी ने कहा कि इसमें चलो। वह मकान हमारे किसी अनुसूचित जाति के भाई का था। उस कमरे में घूसने लगे तो मैं तो चला गया लेकिन देवी लाल जी सात फीट लंबे थे वे घूटने के बल उसके अंदर घूसे। मुझे अंदर ले जा कर बोले कि देखो और उसको बोले कि बता तेरे घर के अंदर क्या-क्या रहता है? रास्ते चलते उन्होंने कहा कि आपने टांक का पानी पिया है। मैंने कहा कि मैंने जीवन में कभी देखा नहीं तो पिया कहां से। वे सड़क के किनारे एक घर में ले गए और बोले कि रस्सी और बाल्टी लाओ। उन्होंने टांका में से पानी निकाला और बताया कि यह टांका कैसे और किस लिए बनाया जाता है और किस तरह लोग इसमें बरसात का पानी जमा कर के गुजारा करते हैं। उनके साथ घूमने के कारण कुछ प्रत्यक्षीकरण हुआ। इसलिए मैं उन नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मुझे भी उन राजस्थानी इलाकों में भ्रमण करा कर, गांव के गरीब, किसान और मजदूर के दुख-दर्द को दिखाया। मैं इस बात को उठाना चाहता हूं कि इसी सदन में इलाके के पिछड़ापन पर कांग्रेस के श्रीमती रत्ना सिंह जी का प्रस्ताव आया, सतपाल महाराज जी का प्रस्ताव आया, श्री रंजन प्रसाद यादव जी, श्री भोला प्रसाद सिंह जी, श्री वैजयंत पांडा जी का प्रस्ताव आया। इसी तरह से अनेक इलाके के साथियों का इसी लोकसभा में क्षेत्रिय विषमताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव आया। इससे संसद में बहस के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि भारतवर्ष में क्षेत्रिय विषमता है, सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है और इन विषमताओं के ऊपर समग्रता में चिंतन कर के अगर निदान नहीं निकाला गया तो भारत के ये सभी पिछड़े इलाके एक न एक दिन विद्रोह की अग्नि की ज्वाला में जलने लगेंगे। इसलिए मैं संसद के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, योजना आयोग पर विश्वास कम है, योजना आयोग न तो मेरे लिए योजना बनाता है और न ही अनुसूचित जाति, किसान, मजदूर, गांव और गरीब के लिए योजना बनाती है। केवल मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए योजना बनाती है। विश्व बैंक से संचालित होने वाले कुछ लोग योजना आयोग में बैठे हैं उनका आजकल बीच में एक नाम आ गया है, यह कन्सलटेन्स कहे जाते हैं। यह जानते होंगे, आज हर योजना में कन्सलटैंट नियुक्त किया जाता है। मैं भारत सरकार के शीपिंग विभाग में मंत्री बना था उसमें कई जगह कंसल्टैंट आया तो मैं सोचता था कि यह कंसल्टैंट कौन प्राणी का नाम है। यह कंसल्टैंट कौन पद है तो कहा गया कि जो बीच में योजना का डीपीआर बनाते हैं और जो योजना का प्रारूप बनाते हैं। मैंने कहा कि इनको बहाल कौन करते हैं तो बताया गया कि जिससे हम कर्जा लेते हैं उसके द्वारा बहाल किए गए हैं। हमने अंतर्ध्यान लगाया तो पाया कि गांव में जिसको दलाल कहते हैं वह यहां पर कंसल्टैंट है। कंसल्टैंट माने वे विश्व बैंक के साथ कंसल्ट करते हैं और योजना आयोग में जा कर कंसल्ट करते हैं। दोनों के कंसल्टेशन में जहां एक मीटिंग प्वाइंट होता है, वह तय कर योजना को पास कराते हैं। विश्व बैंक के कर्जे से योजना बनती है, यह चलती है और बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है यह हम और आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि यह इतने ऊपर का खेल है कि उस खेल को अगर हम देखने लगेंगे तो कितना जन्म लेना पड़ेगा इसका पता नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि भारत की योजना गलत बनती रही है। योजना केवल विकसित इलाकों के लिए बनी है। योजना केवल शहरीकरण के लिए बनाई गई है। योजना केवल शहरों के किनारे विकास के लिए बनाई गई है और जितने शहर बसाए गए हैं, इस दिल्ली में चलइए, पंजाबी बाग, दौलताबाग, मीना बाग और कौन-कौन बाग हैं, यह बाग का क्या मतलब है। यह कभी बाग रहा होगा। यह कभी गांव रहा होगा। यहां कभी किसान रहे होंगे। इस इलाके में जितने अहीर जाट और गुजर खेती करने वाले लोग थे उनकी जमीन छीन ली गई और उसमें बड़ी-बड़ी कॉलोनियां बसा दी गई।

16.00 hrs.

उनके बच्चों को उजाड़कर भगा दिया गया। वे भिखमंगे बन गए, गांव में चले गए, निर्धन-निर्बल बन गए। लेकिन बड़ी-बड़ी कालोनियां बनाई गई, बड़े-बड़े मकान

बनाए गए, बड़े-बड़े अफसरों को गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में सजे-सजाए मकानों में रखवाया गया। ईंट की दीवारें बनीं और उत्तराखंड, हिमालय से लकड़ी काट-काटकर उन दीवारों पर लकड़ी लगाई गई, फर्श के नीचे लकड़ी लगाई गई, छत के ऊपर लकड़ी लगाई गई। श्रीमान्, उस गांव में बसने वाले लोगों के पास खम्बे, छप्पर के लिए लकड़ी नहीं है, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। यहां ईंट के मकान को लकड़ियों से सजाया गया है और वही लोग पर्यावरण की बात करते हैं जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारतवर्ष में इन विषमताओं को मिटाने के लिए समग्रता से चिंतन होना चाहिए। जितनी क्षेत्रीय विषमताएं हैं, हमारे राजस्थान के साथी बोल रहे थे, अगर आप उन इलाकों का सामाजिक विश्लेषण करें, उन अविकसित इलाकों, पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तान या उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र के पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपोल, कटिहार, किशनगंज आदि का सामाजिक परिवेश देखें तो अधिकतर लोग पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के हैं। पहाड़ों, जंगल में अनुसूचित जाति वनवासी बसते हैं। अगर जैसलमेर, बाड़मेर. रेगिस्तानी इलाकों में देखें तो वही लोग बसते हैं जो रेगिस्तान की तपती धूप बर्दाश्त कर सकते हैं, जो उस लू में ठहर सकते हैं। सबसे ज्यादा लोग सीमा पर हैं और वहां आक्रमण भी सबसे ज्यादा होता है। अगर हिन्दुस्तान का इतिहास निकालकर देखें तो यहां जितने भी आक्रमण हुए हैं, सब पश्चिम की तरफ और रेगिस्तानी इलाकों की तरफ से हुए। वहां के लोगों ने उन आक्रमणकारियों से मुकाबला किया। इसलिए मैं इस संसद द्वारा उनके पूर्वजों का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके पूर्वज ऐसे थे जो उस रेगिस्तान में रहे।

सूख रही है बोटी-बोटी मिलती नहीं घास की रोटी

गढ़ते हैं इतिहास देश का सहकर कठिन सुधा की मार

नमन तुम्हें मेरा सतबार।

ऐसे लोग हिन्दुस्तान में रहे हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा की, इसके लिए अपने प्राण गंवाए, आज वे भूखे हैं, उनकी संतान नंगी है, अशिक्षित हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मैं योजना आयोग और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान का मरूस्थली है, रेगिस्तान का इलाका है, बंजर जमीन है, कंकरीली जमीन है, जहां कुछ पैदा नहीं होता, ऐसी गैर-उपजाऊ जमीन में...(व्यवधान) महाबल मिश्र जी,...(व्यवधान) सभापति जी, जरा रोकिए।...(व्यवधान) मंत्री जी के नजदीक आकर लोग डिस्टर्ब करते हैं। संयोग से गुलाब नबी आजाद साहब साथ बैठे हैं। जब हम इस बार श्रीनगर गए थे तो हमने ट्यूलिप गार्डन देखा। गुलाम नबी जी वहां के मुख्य मंत्री बने थे। लोगों ने इनकी प्रशंसा की।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने ट्यूलिप गार्डन बहुत सुंदर बनवाया है।

â€¦(व्यवधान)

16.05 hrs.

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): मैंने इनको धन्यवाद दिया कि जितने दिन ये मुख्य मंत्री थे, वहां कुछ करके आए हैं जो श्रीनगर में लोग इनका नाम ले रहे हैं। मैं ट्यूलिप गार्डन में घूमा तो लोगों ने आपकी प्रशंसा की। हम कांग्रेस पार्टी की शिकायत जरूर करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनकी प्रशंसा भी करेंगे। हम दिनकर जी की राह के राही हैं।

पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधाक्रम है

वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है।

इसलिए हम अच्छे काम करने वाले की पूजा करेंगे।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं कह रहा था कि जो बंजर, पथरीली, कंकरीली, गैर-उपजाऊ भूमि है, जहां विकास नहीं गया, क्या आप उन इलाकों में औद्योगीकरण नहीं कर सकते? इसी संसद में बोलते हुए समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया ने इस प्रश्न को छेड़ा था। उन्होंने कहा था कि जो अविकसित इलाका है, उस रेगिस्तान वाले इलाके, बंजर, पथरीले इलाके में उद्योग खड़ा कीजिए। जब उद्योग लगेगा तो वहां बिजली जाएगी, मकान बनेंगे, अफसर रहेंगे, दुकानें खुलेंगी, चाय की दुकान, पान की दुकान। उद्योग खुलेंगे तो बड़े-बड़े उद्योगपति उसमें मौज करेंगे, अफसर मौज करेंगे, आजाद साहब। लेकिन चाय की दुकान, पान की दुकान, खोमचे की दुकान, छोटे से ढाबे की दुकान चलाकर हमारे बच्चे और बहु-बेटियों को रोजगार मिलेगा। अगर वहां तक सड़कें जायेंगी, तो उस इलाके का विकास होगा। वहां उद्योग किसलिए नहीं बनेगा, क्योंकि वह इलाका विकसित नहीं है। मैं कहता हूं कि वह इलाका इसलिए विकसित नहीं हैं, क्योंकि वहां उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार नहीं है। आप हरियाणा से लेकर सब जगह एनसीआर बनाते हैं दिल्ली के चारों तरफ। एक नम्बर तीन फसला जमीन, उपजाऊ कृषि भूमि को उजाड़ते हैं। जहां कुछ नहीं पैदा होता, उस रेगिस्तान के इलाके में क्या कारखाने नहीं बना सकते, रिफाइनरी नहीं लगा सकते? क्या वहां रेलगाड़ी का जाल नहीं बिछा सकते, सड़कों को नहीं बना सकते, अच्छे स्कूल नहीं बना सकते? नहीं बनायेंगे, किसलिए नहीं बनायेंगे, क्योंकि पोलिटिकल प्रैशर नहीं हैं। वहां वोकल लोग नहीं हैं। जहां पोलिटिकल प्रैशर वाले हैं, वोकल लोग हैं, आवाज उठाने वाले हैं, धरना देने वाले हैं, टीवी, मीडिया में लिखने वाले हैं, उनके हाथ में अपनी कलम है। अंग्रेजी के सभी अखबारों में डिस्पेच पर डिस्पेच लिख देंगे, बंजर को उपजाऊ बना दे, उपजाऊ को बंजर बना दे, यही तो मीडिया का खेल है और यही आज के अखबार का भी मेल है, बाकी हम कुछ देख नहीं पाते हैं।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो अविकसित इलाका है, उसे विकसित करने के लिए योजना आयोग योजना बनाये। क्या कभी योजना आयोग में किसी

एमपी से पूछा जाता है, किसी एमएमलए से पूछा जाता है, किसी जनप्रतिनिधि से पूछा जाता है? योजना आयोग में बड़े-बड़े लोग उसके सदस्य बनते हैं। अर्थशास्त्र के नाम पर मैं उन अर्थशास्त्रियों को चुनौती देना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी को नहीं, प्रणब बाबू अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में योजना आयोग का एक अर्थशास्त्री आये और उसके साथ हुक्मदेव नारायण जैसा अर्थशास्त्र, का साधारण ज्ञान रखने वाला एक किसान बैठे। मेरे साथ बहस करे। मैं योजना आयोग के उस अर्थशास्त्री को एक बार नहीं, तीन बार परास्त कर दूंगा। इसलिए कि उनकी दृष्टि और मेरी दृष्टि में फर्क है। उनकी दृष्टि गरमोन्मुखी, गरीबोन्मुखी, किसानोन्मुखी, पिछड़ान्मुखी, दलितन्मुखी, निर्धन के प्रतिन्मुखी नहीं है। इसलिए कबीर दास ने कहा कि "जो दर्शन करना चाहिए, तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई, तो दरस कहां से पाई।" यह जो हमारे योजना बनाने वाले हैं, उनके हृदय में वह नहीं है। उनके हृदय में गरीब की तस्वीर नहीं है, मजदूर की तस्वीर नहीं है इसलिए भारत का यह इलाका पिछड़ा रह गया और भारत का इतना समाज पिछड़ा रह गया।

सभापति महोदय,. रामचरित मानस की एक-दो चौपाई कहकर मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। हमारे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी बोलेंगे। वे राजस्थान के हैं और सौभाग्य से यह आईएएस अफसर, कलैक्टर साहब भी रहे हैं। इसलिए इन्होंने देखा भी होगा। इनको दोनों अनुभव है। हनुमान जी जब लंका में गये थे, तो उस समय उन्होंने वर्णन किया है --

मंदिर-मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहं-तहं अगनित योद्धा,

गया दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सो नाहि,

सयन किये, देखा कपि तेहि, मंदिर महुं न दीखी बैदेही।।

उसी तरह मैं वर्ष 1959-60 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। ब्लाक का प्रधान बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना। तीन बार विधान सभा का सदस्य बना। लोक सभा, राज्य सभा को देखा। दो बार भारत सरकार का मंत्री बना। मैं गांव से चला था। मेरे पिताजी, आठ चाचा और चार चचेरे भाई स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। मेरी मां मुझे गोद में लेकर अपनी नैहर भाग गयी थी, क्योंकि अंग्रेज ने घर जलाया था। मेरे चाचा जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। प्रथम जिला परिषद के सदस्य बने थे, वाइस चेयरमैन बने थे। मैं उस इलाके की बात करता हूं कि जहां भारत वर्ष की उन समस्याओं को देखा ...(व्यवधान) मैं गांव से चला ...(व्यवधान) ठीक बात है साहब, मैं आपकी तरफ आने को तैयार हूं, बशर्ते कि आप अपनी रेलगाड़ी का इंजन बदल लो, गति दुरुस्त कर लो, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। लेकिन मैं इस इंजन वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा, जिसकी दुर्घटना होने वाली है और मैं जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहता हूं, इसलिए मैं उस रेलगाड़ी पर नहीं बैठूंगा।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मैंने सब देखा, खेत देखा, खलिहान देखा, गांव देखा, निर्धन-निर्बल को देखा, ग्राम पंचायत से लेकर लाल किला तक देखा, सभी को देखा, लेकिन किसी के दिल मे गांव, गरीब, किसान के लिए प्यार नहीं देखा। दिल में दर्द नहीं देखा। आपने अभी घोषणा की थी कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं और सभी प्रखण्डों में मोबाइल वैन भेज रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन अगर वह खराब होगी, तो मरम्मत कौन कराएगा? डीजल कौन देगा, ड्राइवर को वेतन कौन देगा। आप अगर देखिए तो हिन्दुस्तान में सिविल सर्जन के कार्यालय में सबसे ज्यादा गाड़ियां सड़ रही होंगी, करोड़ों रुपये की गाड़ियां पड़ी होंगी। पूछने पर पता चलता है कि वह उस आर्गनाइजेशन की है। श्रीमन्, बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन उसकी परवरिश करना कठिन है। हिन्दुस्तान की नीति यही है कि बच्चे पैदा करते चलो, भला करेंगे राम। योजना हम बनाएंगे, लेकिन उसका पालन करेगी राज्य सरकार। बच्चा है तेरा और दूध पिलाएं हम, बच्चा है तेरा, लेकिन खाना खिलाएंगे हम। हमें अगर बच्चा पैदा करके देते हैं, तो उसकी परवरिश करने का भी इंतजाम कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि हिन्दुस्तान रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। आप राजस्थान में जाएं, बिहार में जाएं, उड़ीसा में जाए, हमारे बिहार में रोज सवेरे औरतें खड़ी होकर काली माई के सामने प्रार्थना करती हैं - अविरल आंसू बहे नैनन से, अब तो कृपा करो, हे काली कृपा करो। उनकी आंखों से निरंतर अविरल अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है, वह पीड़ा है, दर्द है, आप अपने अंदर वह चेतना पैद कीजिए। कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है। अभी हरीश जी बोल रहे थे, मैं गिन रहा था, एक तरफ मांग कर रहे थे, अपनी पीड़ा भी सुना रहे थे और एक दर्जन बार सरकार को धन्यवाद भी दिया। मैंने कहा कि दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा साहब? यह तो गलत बात है। एक बार मैं दुकान में गया, एक डिब्बी को देखकर मैंने पूछा कि इसमें क्या है? उसने जवाब दिया, इसमें स्नो है। मैं खड़ा हो गया। मैं साधारण अंग्रेजी पढ़ा हूं। मैंने कहा - यस होगा, तो नो नहीं होगा। नो होगा, तो यस नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं, यह स्नो है, यह चेहरे पर लगाने वाला स्नो है, पावडर है। मैंने कहा कि कमाल की दुनिया है बड़े लोगों की, यस और नो को एक ही डिब्बी में बंद करते हैं। उसी तरह हरीश हैं, एक तरफ एक दर्जन बार सरकार को धन्यवाद देते रहे और दूसरी तरफ अपने पिछड़ेपन पर आंसू भी बहाते रहे। मैं हरीश जी से प्रार्थना करूंगा कि छोड़ो इस बात को, चाहे सरकार कोई हो, सत्ता कोई हो, गांव के गरीब, निर्धन, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर एक बार उठो, अपनी आंख में शंकर के तृिनेत्र की ज्वाला लेकर निकलो। जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे, उस दिन हम अपनी तृिनेत्र की ज्वाला में इस व्यवस्था को जलाकर राख कर देंगे और उस राख को अपने शरीर में लपेटकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। नया भारत बनेगा तब, गांव-गरीब मजबूत होगा तब।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे श्री हरीश चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प - देश में मरू प्रदेशों के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैंने हरीश चौधरी जी और श्री हुक्मदेव नारायण यादव को सुना, बहुत बृहद् रूप से आपने अपनी बातें रखी हैं, बिल्कुल जमीन और गांव से जुड़ी हुई बातें रखी हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह बात सत्य है कि इसी सदन में विभिन्न अवसरों पर क्षेत्र के विकास, अपने प्रदेश के विकास, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास की बात हम लोग बराबर करते रहे हैं। लेकिन विभिन्न अवसरों पर इस प्रकार की तमाम चर्चाएं हुई हैं, जिसके बारे में अभी हुक्मदेव नारायण यादव जी ने कहा। यह बात सही है कि बहुत से इलाके बहुत पिछड़े हैं। खासकर प्रदेशों की स्थिति अगर देखी जाए, हुक्मदेव जी आज अखबार में एक विस्तृत रिपोर्ट आई है, जिसमें प्रदेशवार चाहे वह बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम प्रदेशों की आर्थिक स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया गया है। हो सकता है आपने यह पढ़ा भी हो। यह दुर्भाग्य है कि अभी तक की सरकारों ने इसके लिए कोई विशेष पहल नहीं की और न ही इन प्रदेशों के लिए कोई कार्य योजना तैयार की। हमारी एक मांग है कि सैनसेक्स की रिपोर्ट जो आती है, उस पर कहीं न कहीं विराम लगना चाहिए, हम लोग नहीं कर पाए, यह एक दुर्भाग्य है।

उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की तर्ज पर हरीश जी ने मरू राज्यों के लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग की है। मुझे नहीं मालूम कि उत्तर-पूर्व राज्यों में कितना पैकेज दिया गया और कितना विकास उससे हो पाया। जब प्रदेशों की बात आती है तो एक तरफ आप देखें कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पूर्वोत्तर राज्य या राजस्थान हैं, इनकी अपनी अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इसलिए हर प्रदेश की अपनी अलग-अलग समस्याएं भी हैं। मैं यह नहीं

कहता कि वहां स्थानीय स्तर पर उनकी सरकारें नहीं बनी हैं। इस देश में दो राष्ट्रीय राजनैतिक दल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हैं। इनकी भी कहीं न कहीं सरकारें हैं। लेकिन जो बात निकल कर आती है, जैसा हुक्मदेव जी ने भी कहा कि कहीं न कहीं राज्यों और केन्द्र के बीच समन्वय की कमी है, वह स्थापित नहीं हो पार है, जबकि वह होना निहायत जरूरी है। यही कारण है कि हमने नियम 193 के तहत इसी मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की थी कि कम से कम सुबह से लेकर शाम तक माननीय सदस्य उसमें हिस्सा लें और अपने सुझाव दें। हम लोगों ने बीएसी की मीटिंग में भी कहा था कि केन्द्र और राज्यों के बीच कैसा सम्बन्ध होना चाहिए, इस पर सदन में चर्चा हो, लेकिन अभी तक वह नहीं हो पाई है। विभिन्न अवसरों पर हम बोलते हैं, लेकिन विस्तृत तरीके से चर्चा नहीं हो पाई है।

मैंने एक चीज देखी है और वह मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं। केन्द्र में जिस दल की सरकार हो, अगर राज्य में उसी दल की सरकार बनती है तो उस राज्य का विकास काफी कुछ सम्भव हो जाता है, लेकिन अगर केन्द्र में और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें हो तो फिर भेदभाव स्वाभाविक है। हमेशा यही हुआ है और यही कारण है कि समय-समय पर मरू प्रदेशों के लिए, पूर्वांचल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए या पूर्वोत्तर के लिए आर्थिक पैकेज की मांग उठती रही है। इस पर कहीं न कहीं विराम लगाना पड़ेगा।

सभापति जी, मेरा तो यह मानना है कि केवल सामाजिक या आर्थिक पैकेज की ही बात क्यों की जाती है, शैक्षणिक पैकेज क्यों नहीं माना जाता है। जब तक किसी राज्य में शैक्षणिक विकास नहीं होगा, तब तक सामाजिक और आर्थिक पैकेज का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक परिवार में अगर एक शिक्षित व्यक्ति होता है या एक मां-बहन शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित बनाने की कोशिश करती है। परिवार में एक के शिक्षित होने से यह संस्कार पूरे परिवार में आ जाता है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक पैकेज के अलावा शैक्षणिक विकास की भी बहुत आवश्यकता है। शिक्षा तो सामाजिक और आर्थिक समस्या के हल की मूल जड़ है। अगर इसका विकास नहीं होगा तो सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता। शिक्षा से ही सामाजिक विकास होगा और सामाजिक विकास से आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा।

मुझे याद है, राजा रामपाल जी शायद चले गए हैं, हुक्मदेव जी आपने भी सुना होगा एक जाति है घूमन्तु, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। इस जाति का न तो कोई घर होता है, न कोई ठिकाना होता है और न ही कोई धर्म या जाति होती है। उन्होंने हमें अपने निवास नार्थ एवेन्यू में बुलाया था, जहां इस जाति के प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने हमें बताया कि न तो हमारा कोई घर है और न ठिकाना। हम लोग घूमते रहते हैं। जहां रुकना होता है, वहां एक-दो दिन के लिए बस जाते हैं और वही उनका निवास हो जाता है, नहीं तो वे घूमते ही रहते हैं। हमारे क्षेत्र में भी और जहां जंगलों में लोग रहते हैं, एक जाति है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वह यादवों और घोसी जाति से मिलती-जुलती है और वे लोग भी दूध, लकड़ी और खेती का व्यवसाय करते हैं। गुज्जर जाति और ऐसी दूसरी घुमंतू जाति हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। इनके विषय में भी सदन में कोई चर्चा नहीं हुई है। भारतवर्ष विभिन्न धर्मों और मजहबों का देश है, विभिन्न वेशभूषा का देश है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग हैं, यहां के उत्पादन भी अलग हैं। कहीं पर किसी चीज का उत्पादन होता है, कहीं पर किसी और दूसरी चीज का उत्पादन होता है। जहां पर ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं उस जगह का विकास हो जाता है। कहीं पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता है और यही कारण है कि हमारे यहां पर नक्सलवाद पनप रहा है, आतंकवाद फैल रहा है या क्षेत्रीयवाद फैल रहा है। चाहे बोडो-लैंड हो या दूसरी चीजों से जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा है और ऐसे लोग सिर उठाकर सांप की तरह फूंफकार रहे हैं लेकिन उस ओर हमने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। उसका कारण क्या है, हमने इस विषय में कभी सोचा नहीं है। उनके यहां इसीलिए कोई विकास नहीं हो पाया है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उनके यहां कोई विकास नहीं हुआ है।

माननीय मुलायम सिंह जी जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो हमारे सोनभद्र साइड से शिकायतें बराबर आ रही थीं। वहां 19 साल की एक लड़की लीडर थी। अधिकारी मना कर रहे थे लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि कारण क्या है, क्यों ऐसी स्थिति है? हमारे प्रदेश में दो-चार जगह ही नक्सलवाद है, जबकि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। जब वहां इनका हेलीकोप्टर उतरा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। जब एनाउंसमेंट हुआ तो थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है और अपनी भाषा में आवाज देती है, तो हुक्मदेव जी आपको विश्वास नहीं होगा कि हजारों की संख्या में वे लोग इकट्ठे हो गये जो विद्रोह कर रहे थे, जो समाज की मुख्यधारा से अपने को अलग समझते थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जंगल में रहते हैं, यहां न कोई सड़क है न अन्य कोई सुविधा। माननीय किशोर देव जी, आपने देखा होगा कि आदिवासियों की यही समस्या है। जो लोग जंगलों में रहते हैं, आपने गुज्जरों और घुमंतू लोगों की बात आपने कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहां न तो सड़क है, न कोई पाठशाला, न हमारा नाम वोटर लिस्ट में है, न हम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं, न हम जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, हमारे यहां कुछ नहीं है। हम लोग जंगलों में रहते हैं और इसीलिए हम लोगों ने हथियार उठा लिये कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे यहां कुछ विकास नहीं हुआ है। वहीं पर जो-जो उनकी मांगे थीं, मानी गयीं और वह लड़की आज समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से कहीं न कहीं बात करनी पड़ेगी। इसी सदन में कहा जाता है कि हम ताकत से निपटेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें उनसे जाकर उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, वे क्यों समाज की मुख्यधारा से अलग हैं। उनके दर्द और पीड़ा को जब हम जानेंगे तभी आप जाकर कुछ कर सकते हैं। जब आप कुछ करेंगे तभी आपके यहां यह नक्सलवाद, आतंकवाद समाप्त होगा और आंतरिक सुरक्षा आप कर सकेंगे।

माननीय हुक्मदेव जी आप इलाहाबाद भी गये होंगे। वहां का अपना एक इतिहास रहा है। मेरे क्षेत्र में एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना है, आप सभापति महोदय विश्वास करिये कि जिन लोगों का पुश्तैनी धंधा था उन लोगों को उनके पुश्तैनी धंधे से, रोजी-रोटी से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अगर कुम्हार हुआ तो उसे मिट्टी का पट्टा दिया जिससे वह अपना जीवन-यापन कर सके। अगर निषाद, मल्लाह हुआ तो उन्हें पट्टा दिया घाट का, मछली का, जिससे वे अपनी रोजी से जुड़ सकें। आज वहां स्थिति यह है कि जितने बालू-माफिया हैं, भू-माफिया हैं, इन लोगों ने कब्जा किया।

वहां मजदूरों से खुदाई कराई जानी चाहिए, लेकिन जेवीसी मशीन लगा कर खुदाई होती है। यही कारण है कि वहां लाल सलाम सेना बन गई है। लाल सलाम के नाम पर वहां पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी खड़े नहीं रह सकते हैं। हर समय वे हाथों में अवैध असला लिए रहते हैं, जिन पर पाबंदी है और हमारे यहां जिन्हें तमन्चा या कट्टा बोलते हैं। उन्हें पुलिस कुछ नहीं कहती है। शहरों में यह सब पनप रहा है। कल टीवी पर बुंदेलखंड में बांदा जिले में आपने गुलाबी सेना देखी होगी। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार या बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए गुलाबी सेना बनी है। उनकी साड़ी गुलाबी रंग की रहती है और हाथ में डंडा होता है। वे अधिकारियों के यहां पहुंच जाती हैं, यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान को अपना कार्यालय छोड़ कर भागना पड़ता है। यह स्थिति आज वहां है। जब शहरों और इलाकों से, जहां से देश को चार-पांच प्रधानमंत्री मिले, वैज्ञानिक मिले, आईएएस और आईपीएस मिले वहां की स्थिति ऐसी है। वे मांग कर रहे हैं कि हमारी ये जरूरतें हैं, हमें रोजी-रोटी की तलाश है। हमारी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति अच्छी की जाए और हमारे स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो पुश्तैनी धंधे चल रहे थे, वे हमें मिलें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यही कारण है कि आज नक्सलवाद और आतंकवाद पनप रहा है और सेनाएं बन रही हैं। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सीमाओं पर भी देश को खतरा है, लेकिन आंतरिक खतरा भी है।

महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पैकेज की जो मांग उठती है, वह स्वाभाविक है। यह कारण केवल उनकी गरीबी, लाचारी, बेबसी और जो उनका शोषण हो

रहा है, इस कारण उन्होंने सेना बनाई है। यही कारण है कि आज जब उन्होंने हथियार अपने हाथ में उठा लिए तो वे लड़ने के लिए मजबूर हैं। आप उनके साथ बात क्यों नहीं करते हैं? आपको उनके साथ बात करनी चाहिए। कई बार हमने सदन में मामला उठाया कि उनके साथ गृह मंत्रालय की टीम जा कर उनसे बात करे। वहां लोकल पुलिस जरूर उनसे निपटती है, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। बीपीएल की बात बहुत विस्तार से हुक्मदेव नारायण जी ने कही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो गरीबी, गुरबत, लाचारी, शोषण हुआ है, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी हैं, जिन पर जुर्म और अत्याचार हुए हैं, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अंग्रेजों ने भी लिखा है, जो बहादुर और स्वाभिमानी कौम रही, जैसे पासी बिरादरी है। बहुत सी ऐसी जातियां रही हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने देखा कि ये बहुत बहादुर और स्वाभिमानी कौम रही हैं और ये सीने पर गोली खाते हैं, पीठ पीछे गोली नहीं खाते हैं, उन्हें जरायम पेशा और क्रिमिनल एक्ट में रख कर गए। ऐसे लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की बात करनी पड़ेगी। उनके बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा, तभी हम आर्थिक विषमता दूर करने में सफल हो सकते हैं।

इन्हीं बातों के साथ मैं श्री हरीश चौधरी द्वारा लाए गए संकल्प का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं श्री हरीश चौधरी द्वारा लाए गए संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मरुस्थल में रहने वाले जो लोग हैं और वहां जो भोगौलिक विषमता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण वहां विकास नहीं हो पाता है, उसके विकास के लिए मैं पुरजोर कहना चाहूंगा कि वहां नार्थ-ईस्ट की तरह एक आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिससे मरुस्थल का विकास हो सके। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम मरुस्थल को स्टडी करें कि वह कैसे बना है, क्योंकि मुझे जैसलमेर और बाड़मेर जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि कोई मीटोराइट वहां आया और एक उल्का धरती से टकराई, तो जो इलाका पहले बहुत ज्यादा लग्रीन था, बहुत ज्यादा वैंजिटेशन थी, बहुत ज्यादा सब्ज था, बहुत ज्यादा उपजाऊ था, लेकिन किसी उल्का के टकराने के कारण वहां सारी चीजें इवापोरेट हो गई और आप अगर जैसलमेर का पत्थर भी देखेंगे, तो वह ऊपर से तो काला होता है, लेकिन नीचे से सफेद होता है। वहां मुझे पेट्रोफाइड राक देखने का मौका मिला, जिसके लिए लोग कहते हैं कि बड़ी गर्मी से वहां की लकड़ियां पत्थर की तरह बन गई हैं। जिसके लिए वहां पर किवदंती है कि किसी ऋषि ने श्राप दिया और सारे पेड़ पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गये। वह एक साइंटिफिक कृम था कि जब लिथरॉइट टकराता है तो पूरा स्थान एक डेजर्ट का रूप ले लेता है। वही स्थिति हमारे इस डेजर्ट के इलाके में है और उस डेजर्ट के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आज इजरायल और दुबई में बहुत से ऐसी टैक्नीकल चीजें बनाई हैं।

आप देखेंगे कि रेत के ऊपर उन्होंने घास को उगा दिया है और ऐसे ऐसे ग्रीन हाउसेज बनाये हैं जिसमें हर किस्म की फसल को आज वे दुबई के अंदर उगा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए वह टैक्नोलॉजी लाई जाए चाहे उस पर जो भी साइंटिफिक उपाय से फार्मिंग हो सके, वह की जाए। इसके साथ साथ डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी है। स्पेन इस पर बड़ी टैक्नॉलोजीकली आगे बढ़ा है और स्पेन ने सोलर एनर्जी को वहां बहुत ज्यादा प्राप्त किया है। डेजर्ट के अंदर इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा की वहां पर स्थापना का जी सकती है ताकि हम अपने डेजर्ट से शक्ति प्राप्त करें। आज डेजर्ट में हवा बहुत तेजी से बहती है। इसमें विंड टरबाइन लगाकर बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। डेजर्ट का जो पिछड़ा इलाका है, वहां से अगर आप ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से वहां विकास होगा। इसके साथ साथ इसमें नम्बर दो पर लिखा है कि इन प्रदेशों में जो लोग रहते हैं, अन्य भागों के लोगों के साथ उनका सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त होना चाहिए यानी वे जो भारत के जो अन्य क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि जब तक हमारे आर्थिक आरक्षण की नीति नहीं बनेगी, आर्थिक रूप से आरक्षण की बात हम नहीं सोचेंगे, गरीबी को हटाने का हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो आपकी विंड टरबाइन्स हैं, जो सोलर सिस्टम है, इसका विकास होना चाहिए। रेल का विस्तार होना चाहिए। मैं जब रेल राज्य मंत्री था, उस समय मेरे पास एक फाइल आई थी कि आप पोखरन के स्टेशन को हटा दीजिए। परंतु मैंने कहा कि पोखरन का स्टेशन समाप्त नहीं होना चाहिए। उसको हमने बरकरार रखा क्योंकि हम चाहते थे कि मरुस्थल का विकास हो। मरुस्थल आगे बढ़े। पोखरन वह जगह है जहां पर हमने एटोमिक एक्सप्लोजन किया है और वह अपने आप में एक हेरिटिट साइट है। इसको देखते हुए जब हम रेल का विस्तार करेंगे क्योंकि मरुस्थल के अंदर जो रेल चला करती थी, आपके जैसलमेर के अंदर, वह एक टायर पर चलती थी, रेलवे की पटरी पर चलती थी। अर्थात् वहां के डिब्बों में जो कार के टायर भी लगे होते थे। परंतु आज बड़ी तेजी से वहां रेल जा रही है और विकास हो रहा है। इसके साथ साथ वहां पर सोलर फोन्स लग जाएं तो अगर कोई एसओएस करना चाहता है कि कोई संकट में पड़ जाए, कोई एमरजेंसी में पड़ जाए तो सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होगी और उससे आप कहीं से भी कभी भी टेलीफोन कर सकते हैं। इसी प्रकार के सोलर टेलीफोन्स आपको यूएई में देखने को मिलते हैं, आपको दुबई में देखने को मिलते हैं। बड़ी आसानी से ये लग सकते हैं और इस मरुस्थल के नीचे बड़ा खनिज भंडार है। वहां का एक पत्थर है जिसका स्वाद नमकीन होता है और दही जमाने में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उस पत्थर को डाल देते हैं। वहां पर कूड ऑयल, गैस का बहुत बड़ा खजाना है। वहां की क्षमताओं का अनुसंधान करना होगा जिससे हम समझ सकें कि हमारे मरुस्थल के नीचे क्या क्या खजाना दबा हुआ है। उसके लिए एक्सप्लोरेशन की बड़ी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सकल पदार्थ हैं जग में ही और कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ होने के बाद अगर हम कर्महीन हो जाएं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आर्थिक पैकेज के साथ साथ हमें कर्मयोगी भी बनना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां से गंगा बहती है।

गंगा के देश का रहने वाला हूं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और उस देश से जहां से गंगा आती है, वह गंगा यह शिक्षा देती है क्योंकि गंगा धरती की धारा नहीं थी, इसको वैतरणी कहा जाता था, यह स्वर्ग में बहती थी परंतु भागीरथ जी ने तपस्या की और स्वर्ग को भी धरती पर उतार कर ले आए, गंगा को धरती पर ले आए जो आज हमारी धरती को स्वच्छ और निर्मल बनाती है।

अंत में, मैं यही कहूंगा:

"रानी की रवानी बदलेगी,

सतलज का मुहाना बदलेगा,

गर शौक में तेरे जोश रहा

तस्वीर का जामा बदलेगा,

बेज़ार न हो, बेज़ार न हो,

यह सारा फसाना बदलेगा,

कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें,

तब तो यह जमाना बदलेगा।"

हरीश चौधरी जी के संकल्प के साथ उनका समर्थन करते हुए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए

मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity. I welcome the initiative taken by the hon. Member, Shri Harish Chaudhary, for the social economic development of desert region through special economic package on the lines of North-Eastern region.

The hon. Members who spoke before me on this subject have drawn the attention of the Government on the need to provide liberal financial assistance to the less developed regions.

Sir, it is really an issue of extreme concern. People living in the desert region are suffering a lot. Economic opportunities for a decent living are minimal in that region. They have been exploited by various forces and the benefit does not reach them often. The welfare and special programmes to uplift them do not reach them fully. Hence, as advocated by other Members, the Centre has to pay more attention to the socio-economic development of these people in desert areas through special economic packages.

Sir, our country is having two faces, one side with haves and the other side with have-nots. Similarly, we have less developed States and also developing States. We are in a position to take care of both, less developed and developing States. States have more responsibilities for the development of the area. Both the sources of revenues are slowly shrinking. Most of the tax bases and sources lie only with the Centre. Gradually, the Centre is taking away much of the States' power now. The States are reduced to almost glorified municipalities, as our hon. Chief Minister of Tamil Nadu stated. So, the Centre should come forward to extend its helping hand towards the developing States also to meet their demands in a just and fair manner. While showing more attention towards the less developed States, developing States also should not be neglected.

At this juncture, I deem it my duty to draw the attention of the Centre to the needs of the people of Tamil Nadu. My revered Leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puruchi Thalaivi has launched 'Tamil Nadu Vision 2023', document envisioning to increase States GDP at a growth rate of 11 per cent or more per annum. In the words of my revered Leader:

> "Tamil Nadu Vision 2023 is a scheme designed to bring about socio-economic changes and improve necessary infrastructures needed for rapid economic development of the State."

The required investment of Rs.15 lakh crore, as the hon. Chief Minister of Tamil Nadu says, will have to come from States, Centre and private sources.

At this juncture, I would request the Centre to be more liberal and supportive to the efforts of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu in transforming Tamil Nadu into one of the best States in India. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, as we all know, has sought financial help from the Centre to the tune of Rs.1,82,402.18 crore for the various development schemes. I am sorry to say that nearly ten months have passed Centre's response is not only subdued but a mute one. Am I to call it gross-negligence, discriminatory or indifference? While the Government knowingly allowed some persons to cause heavy loss to the Exchequer to the tune of Rs.1,75,000 crore, why not Centre fulfil its commitments of helping the States facing severe financial difficulties?

MR. CHAIRMAN : The subject of the Resolution is 'Special Package for Desert Region'. Come back to the subject. State-Centre is not the subject.

SHRI S. SEMMALAI : Sir, I am supporting the Resolution, but I am asking that the developing States should also be given due attention.

Hence I make a special appeal to the Centre that the financial needs of Tamil Nadu, as articulated by my Leader, be looked into and whatever is needed, the Centre should come forward and extend the assistance.

In this context, I welcome and support the Resolution moved by the hon. Member.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir. Whatever we are discussing today, if the discussion on this Resolution concludes, I hope the mover of this Resolution also will be here to withdraw that Resolution on the request of our hon. Minister who is going to give reply on behalf of the Government.

But the mover of this Resolution, our friend, Mr. Harish Chaudhary, has two specific requests to make to the Government and that request is overall development of desert region in comparison to the economic package that is being provided to North-Eastern States. The second is socio-economic development at par with people living in other parts of the country. These are the two major aspects on which he has been harping on.

I would fail in my duty if I do not mention here that this Resolution was moved on 26th August 2011. The Winter Session has passed, the first part of the Budget Session has also passed and Mr. Harish Chaudhary was unlucky that every time whenever this Resolution was supposed to be discussed, somehow or other it got delayed and delayed.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): This is the fate of all Private Members' Bills and Resolutions.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, this is the fate of all Private Members' Business that has been happening and to some extent we being members of the Business Advisory Committee, also are party to that. Today is 4th of May and perhaps many Members, who at that point of time had showed interest to participate in this discussion, perhaps, have become very tired.

But I remember, human civilization has always excelled when they are put to a lot of difficulty by nature. When nature provides or puts the human kind in difficulty, the intuitiveness of human nature blossoms and one gets the force to tide over that situation. It has happened in the coastal region of very many nations. It has happened in the Island nations of this world. It has happened in the forest or the outer reaches of mountains and it has also happened in the desert regions of this world.

India being a sub-continent, I remember always, I have tried to mention this that when my daughter was in Class V, she came running one evening and showed me the Geography book and asked me, why this piece of land, country, which we call India, this piece of South-Asia, this region is called sub-continent? Why is it a sub-continent? That was being taught to her in Class V or VI.

Why is it a sub-continent? Is it the land mass that is why it is a sub-continent? If we compare it with China, China has bigger land mass, but it is not called sub-continent. Europe has many countries within and that land mass is also less than South Asia. It is called a Continent. Why this is a sub-continent, part of Asia?

It was a question which never confronted me when I was studying. But that question was posed to me by my daughter and I tried to explain that this is a region, this is an area, this is a land mass which is multi-lingual and multi-cultural.

It has mountains. It has sea, bay and ocean. It has desert; it has forest. It has large rivers. It has different types of people living in this part of the region. That is why it is a sub-continent. It is because it is a part of the Asia continent, it is a sub-continent. That is not prevalent in China. It is not prevalent in other parts where so many divergences are not there.

Especially when I come to this desert region, as our friend Shri Arjun Ram Meghwal had educated me especially on this region, I would like to take his help. Jaisalmer, Barmer and Bikaner are the regions which we can identify with desert area. The moment we try to remember those areas, immediately the music and the art come to our mind which is unique in the Indian mosaic. The literature of Bhakti Movement also flourished in that area. At that point of time, when the large part of this nation was being subjugated, the Indian culture was being trampled upon, at that time this desert area flourished in Bhakti Movement because of Meerabai. Arjun Ram Meghwal *ji* also told me the story of Dhola Maru. I think, when he is going to speak, he is going to narrate that pathetic and emotional experience about these two characters. Many people of this country know about Romeo and Juliet. Many people know about the other incidents, the love episodes, which had happened across the border. But the story of Dhola Maru, the amount of affection, goodwill and whatever comes in that love life can only come from a desert region.

One also remembers the historic character of Maharana Pratap and also remembers the day when he was moving in the jungles after being banished from his kingdom. When the child was being provided by the mother with a *roti* of grass and some other things, suddenly a wild cat jumped in and took that *roti* from the hands of that boy. The tremendous emotional pressure, the mental agony that Maharana Pratap had faced in that time of turbulence, it can only be felt by a father when he is unable to feed his children.

One also remembers the depredations Humayun had to undergo when he passed through the desert parts of Gujarat and Rajasthan while going towards Lahore. He took that desert route. What had happened during that period is not a part of History textbooks but it concerns anybody who wants to understand about an Emperor who was given all charge to rule by his father, who had fought shoulder to shoulder with his father in the First War of Panipat and had to leave Delhi because of Sher Shah Suri's aggression. He could come back to Delhi and become Emperor again after the tribulations which he went through for more than 20 years.

I also want to remember the valour of Gadia Lohar. The valour of that tribe needs to be propagated in our country. It is necessary to check the migration of that area. When one talks about the desert area of this region, one also remembers about the Shekhawaties. The best talented entrepreneurship has come from that area – the *Birlas*, the *Bajajs*, the *Goenkas.* They are from that area alone.

I am also reminded of Maharaja Ganga Singh of Bikaner, who was the first President of Indian Chamber of Princes, which is now known as Rajya Sabha.

I am also reminded the work that was done by Shrimati Indira Gandhi to bring water to that area. Today that Nahar has been called as Indira Nahar.â€¦ (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): नहर गंगा सिंह जी लाये थे।

श्री भर्तृहरि महताब : नहर गंगा सिंह जी लाये थे, पर उन्होंने उसे विस्तारित किया था।

When one goes through that area one can see how that has developed. I am also reminded that during Vasundhara Raje's Chief Ministership there was a huge cloudburst. Those areas had tones and tones of water but it did not sink in. Nobody knew what to do with that. At that time Sardar Buta Singh was also representing a part of that area called Jalore and the amount of difficulty the people had to face due to that natural calamity was something which needs to be addressed too.

I would have been happy, if the Minister for Forests and Environment would have been present here today and participated in this deliberation. There is a need to protect flora and fauna of that area. It is by protecting the environment that we protect ourself, the human race.

Mr. Choudhary has also mentioned during his deliberations that schools should be established to develop the traditional skills. He mentioned about schools. Schools should be established to develop skills. I would also request the Minister that today, there is a need in this country that we should give certificates, not only certificates, graduate certificates, under-graduate certificates, to those students who excel. We have to prepare a curriculum for making bell metal, potteries, handloom and handicraft. This type of graduation and post-graduation certificates should be given and a curriculum should be prepared. It will not only encourage them to do their traditional jobs; traditional artefacts; but also it will check migration to the cities. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

...(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I have another two points to make.

Mr. Choudhary has mentioned about the oil and gas that is there in Barmer area. I was told that per day the capacity would be Rs. 1,600 crore. That much of oil and gas is available there which can be explored and exploited in this area. The area of Jaisalmer, Barmer and Bikaner not only has the oil and gas but it has gypsum, marble and phosphate. That amount of money and that amount of wealth, this desert area can provide to the nation. At least a fraction of it can also be invested in that area and for that Mr. Choudhary or anyone do not have to ask for any special package. I think that idea is hidden when he said 'at par with North-East'. When oil is being extracted from North-East, a portion of it is being invested for the development of the North-East. If this type of natural resource is prevalent in that area, why can we not exploit that region and also invest for the development of this region?

I would like to make two more points. Recently when the hon. Speaker had been to New Zealand â€¦...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. Your time is up.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am concluding with these words.

Recently when the hon. Speaker was in New Zealand, she insisted that we should visit a farm and I was thinking in my mind that perhaps she wants to go to a dairy farm or to a lamb farm just to see how wools are made, how cheese or other things are made. But when we arrived at the farm, it was a wind farm. That type of wind farm can also be established in this desert area. For that, I am not insisting that it should be a Public Private Partnership. That can be. But first why do we not allow private enterprise to also go into this area and create wind farm for a specific period?

16.56 hrs (Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

At the same time, we can have the solar energy, the non-conventional energy. This will be a repository of the non-conventional energy. In that respect, I think, Barmer, Jaisalmer and Bikaner can be developed to a very great extent, and the desert will not be a curse on the polity of this nation but it can also become one of the major wealth generating regions of this country.

With these words, I support the Resolution that has been moved by Shri Harish Choudhary.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे प्रिय भाई साहब श्री हरीश चौधरी जी ने जो रेज़ोल्यूशन मूव किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

महोदया, आज इस देश में ऐसे इलाके हैं और जो उन्होंने अपने इलाके की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर की जो हालत है, ये इतने सख्त एरियाज़ हैं कि यहां लोगों का जीना, आज के ज़माने के मुताबिक नहीं है। ज़माना बदला, लेकिन ये इलाके नहीं बदल पाए, क्योंकि यहां की डेवलपमेंट नहीं हो पायी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी मैम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट्स का एमपीलेड एक जैसा है। लेकिन जब एरिया की बात आती है, तो सभी का एरिया अलग-अलग है। क्या इस तरीके से देश की डेवलपमेंट होगी कि एक एमपी का एरिया नहीं देखा, बल्कि उसकी पॉप्यूलेशन को देखा। आप मुझे बताएं कि 25-25 हजार स्कवेयर किलोमीटर की कांस्टीट्यूंसी भी कोई कांस्टीट्यूंसी है। ये तो देश हैं। हमारी दिल्ली की सारी कांस्टीट्यूंसी के सारे एमपी बीस बार जोड़ने पर भी मेरी कांस्टीट्यूंसी के बराबर नहीं पहुंचते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे एमपीलेड और जय प्रकाश जी और इन सब का, जो बाद में मंत्री भी बनते हैं। ये मंत्री भी यहीं के बनते हैं, घूम-घाम के आपको तो पता है। लोगों के साथ और इलाके के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, उसका एक कारण है। जिस एरिया में आपको दो सौ किलोमीटर के अंदर चार घर दिखेंगे, जो इस देश में रहते हैं, क्या उनका पानी पर हक नहीं है, क्या उनका हक बिजली पर नहीं है, क्या उनके बच्चे स्कूल नहीं जाने चाहिए, क्या उन्हें अस्पताल की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? अगर आप उन्हें कहते हैं कि वे भी भारतीय हैं, तो एक भारतीय का दूसरे भारतीय के साथ फर्क क्यों रखा जा रहा है? मेरा कहने का मकसद है कि लद्दाख हिमाचल प्रदेश से बड़ा है और सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र है। आपको हैरानी होगी कि उसका विकास कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ एक एमपी उसका विकास नहीं कर सकता है। आप एमपी को भी पांच करोड़ रुपया दे दीजिए और जब फंड्स देने की बात आती है, तो आप एक कांस्टीट्यूंसी समझ कर पैसा देते हैं।

17.00 hrs.

इसका डेवलपमेंट भी प्लानिंग कमीशन करता है। वह आबादी देखता है कि कितनी है। पहले हम ज्यादा से ज्यादा आबादी वाले को देते हैं। बाकी जो बचे हैं, उन्हें बाद में देखा जाएगा। बचेगा तो उन्हें देंगे, नहीं तो नहीं।

मेरी ज़नाब से विनती है कि आप मेरी अपनी कंस्टीट्यून्सी को देखें तो उसमें सात जिले हैं और 23000 वर्ग किलोमीटर की कंस्टीट्यून्सी है। इसमें खुश्की से, प्लेन से लेकर फिर कंडी, फिर छोटी पहाड़ी, फिर बड़ी पहाड़ी और जाते-जाते हिमालय तक मेरी कंस्टीट्यून्सी पहुंचती है। मुझे बताएं कि जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलिटैन्सी कहां थी? वह डोडा में थी। There was no connectivity; there was no road. ज़नाब आप ध्यान से देखिए कि जब ग्यारह हजार सात सौ वर्ग किलोमीटर का एक जिला हो और उस जिले में आप कहेंगे कि दस प्रतिशत वहां की कनेक्टिविटी हो तो आप हिसाब कीजिए कि ग्यारह हजार में से कितनी सड़कें रहेंगी? वह सड़क जो कश्मीर को जाती हैं ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : इस रिजॉल्यूशन को एक घंटा का समय दिया गया था। वह तो समाप्त हो गया। अगर सदन चाहता है तो इसे एक घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

चौधरी लाल सिंह : मैडम, मैं कह रहा हूं कि वह जिला कहां से कनेक्ट हुआ? वह हुआ पथरीडाब से। वह नेशनल हाईवे है और वह सड़क बीच से बनिहाल से निकलती हुई चली गयी और टनल क्रॉस करके कश्मीर पहुंच गयी। लेकिन, जो बतोश से डोडा, किश्तवाड़, इन्दूवाल, सोती, गुंदो वलेसा, गांधारी, इश्तारी, संसारी, सुमचान इत्यादि क्षेत्र हैं जहां पचास किलोमीटर से ज्यादा का पैदल रास्ता है। मेरा इलाका मारवा, बाड़वंक, इच्छन है जहां 86 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां के गरीब लोगों ने उन इलाकों में रहकर कौन सा जुल्म किया हैं? हमारा इलाका इतना सुन्दर है। वहां लश ग्रीनरी, देवदार के पेड़ हैं, और इतनी अच्छी आबादी है, लेकिन वहां रहने वालों की रोजी-रोटी की हालत इतनी खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां बर्फ गिर रही है। पिछले दिनों पन्द्रह-पन्द्रह, अठारह-अठारह फीट वहां बर्फ गिरी और कई घर दब गए। पिछली बार 40 लोग मरे थे। मेरी आपसे विनती है कि यह जस्टिस का सवाल है। यह श्री हरीश चौधरी का सवाल नहीं है। यह सवाल है जस्टिस और इंसाफ का कि एक इलाके का एरिया और उसकी हालत नहीं देखते और दूसरा इलाका जहां की गलियां भी पक्की हैं, नालियां भी पक्की हैं, रास्ता भी पक्का है, हॉस्पीटल हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट भी है और सारा कुछ है और यहां भी उसी के बराबर पैसा दिया जाता है। यह क्यों है, आप मुझे बताएं। आप उन इलाकों के साथ क्यों नहीं इंसाफ करते जो इलाके आपकी प्लानिंग की वजह से पिछड़े हुए हैं। चाहे वह आपकी सरकार हो या मेरी सरकार हो, सबका ध्यान उसके सामने जाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। मेरे एरिया का रास्ता इतनी दूर खड़ा है कि वह आपको दिखेगा ही नहीं। मैं उड़ीसा गया था। वहां घूमा। वहां की भी बुरी हालत देखी। राजस्थान देखा, उसकी भी बुरी हालत देखी। मेरी कंस्टीट्यून्सी की भी बुरी हालत है। इससे लगा कि जो दिल्ली से दूर है, उसकी बुरी हालत है।

मैडम, आपके साउथ का एरिया इसलिए डेवलप हुआ कि वहां अंग्रेज पहले घुसे। वे वहां से घुसते-घुसते आए। जो-जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, कहीं रेल की, कहीं से माल ढोने की, उन्होंने बनाया। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं बनाया। जहां अपनी सुविधा के लिए रास्ता चाहिए था, उन्होंने अपने लिए सब कुछ किया। इधर मरूस्थल में जाकर उन्हें क्या करना था? पर, अब तो हमारा देश है। अब तो हम इंडियन हैं। अब तो अपने हिन्दुस्तान को हमें देखना है। उसकी जरूरत थी लूटना, हमारी जरूरत तो बनाना है, हमें तो देश बनाना है।

मैडम, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप सुन कर हैरान होंगी कि मेरा जिले रियासी में आप देखेंगी, वहां मोर, अंगराला, गुलाबगढ़ और गुंजाली है। मैं वहां जिले में बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रहा था, मैंने वहां एजुकेशन का स्तर देखा तो मुझे पता चला कि वहां एक जिले में 47 परसैंट अनपढ़ लोग थे। ये इस गलतफहमी में हैं कि हमें बहुत पैकेज मिले। हमें भी 24हजार करोड़ दिखाए, हमें भी बड़े लम्बे-चौड़े पैकेज देने के लिए कहा, लेकिन कुछ नहीं दिया।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे 47 परसैंट बच्चे अनपढ़ हैं तो ये पैसे कहां लगे, कहां गए? इन्हें कौन चैक करता है, इसे कौन देख रहा है? जितना मर्जी पैसा आए, जब उसके ऊपर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और जो आदमी इस देश की सेवा के लिए खड़ा है, जब तक वह उसे देखेगा नहीं, चैक नहीं करेगा, उसे इसकी पावर नहीं होगी, ऐसे आपको कौन पूछता है। आप पूछेंगे नहीं तो वह स्कूल नहीं खुलेगा। आप स्कूलों की हालत देखिए। वहां न चाक है, न टाट है, न बोर्ड है और न ही स्टॉफ है। हम जानते हैं कि वहां टीचर्स भी ठीक से नहीं हैं। सरकारी स्कूलों की हालत तो इस कद्र है, मैं समझता हूं कि सरकारी स्कूल तो गरीबों के लिए नरक बने हुए हैं। गांव की सभी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वहां प्राइवेट स्कूल तो होते ही नहीं हैं और उन लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है, वे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। वहां जो बड़ा आदमी होता है, वह अपने बच्चे को बोर्डिंग में बाहर भेज देता है। आप मुझे बताएं, उन गरीब बच्चों का इस देश में कब उत्थान होगा? आप गुजरों की बात कर रहे हैं, आपने स्पेशल्स केटेगिरी को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया, लेकिन उनकी दुर्दशा नहीं सुधर पाई, क्योंकि कुछ प्लानिंग ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है। वह गुर्जर भैंस ही चरा रहा है। वह गर्मी में नीचे और सर्दी में पहाड़ से पांच-पांच सौ, हजार-हजार किलोमीटर अपनी भैंस को पालने के लिए पैदल जाता है। उसका अन्य कोई काम नहीं है। उसकी बुरी हालत है। उसे कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बच्चे को कौन मोबाइल टीचर देगा, डाक्टर देगा। आपका क्या सिस्टम है, क्या प्लानिंग है? किस प्लानिंग के तहत वह जाति ऊपर उठेगी? कैसे वह बकरवाल आगे आएगा? मैं एक दिन किसी गांव में चला गया। बकरवाल एक कास्ट है, ये मुस्लिम हैं, गरीब हैं। ये जंगलों में रहते हैं। मैंने उनके पास जाकर कहा कि आपने क्या बनाया है। मैं उनकी किचन के अंदर गया। वहां एक औरत खाना बना रही थी। मैंने उससे कहा कि इसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ था। वह सिर्फ पानी को ऐसे ही हिला रही है, उसमें उसने कुछ भी नहीं डाला हुआ था। इस देश के उन गांवों के लोगों का क्या हाल है। मैंने एक घर में जाकर देखा, वहां एक औरत अपने तीन बच्चों को ठंड में ऐसे ही लेकर बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा चौथा बच्चा कहां है, तुम तो कह रही थी कि मेरे चार बच्चे हैं। उसके घर में छत तक नहीं है, वहां से हवा गुजर रही है। मैंने उसके बच्चे को देखा, वह छिप कर बैठा हुआ था। आप सुन कर हैरान होंगे, मैंने उस बच्चे को कहा कि तुम खड़े हो जाओ तो वह खड़ा हुआ। उसकी उम्र 12साल की थी। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, वह पूरा नंगा था। उसे समझ थी कि मैं नंगा हूं। उसे लगा कि कोई आया, उसने छलांग लगाई और वह पीछे छिप गया। वह लड़का बड़ा होता जाएगा, उसके कॉंप्लेक्स को कौन खत्म करेगा। उसके दिमाग के प्रेशर कौन खत्म करेगा। उस बच्चे की सोच को कौन बदलेगा। वह बच्चा कैसे अपने आपको समझेगा कि हम फ्री माइंड हैं।

मैडम, आप एक तरफ देखें कि एक बच्चे के पास कपड़ों की लाइन लगी हुई है, उसे पता ही नहीं कि कौन सा कपड़ा पहनना है और ये इतने नंगे हो गए हैं, इन्हें पता ही नहीं कि कपड़ा पहना है या नहीं पहना है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : लाल सिंह जी, बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

चौधरी लाल सिंह : बाकी माननीय सदस्य भी खूब बोलें, मैं उनके लिए बैठा रहूंगा। आप टाइम बढ़ाते रहें और सुनते रहें।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ तो सीमा होती है।

चौधरी लाल सिंह : अगर सच्चाई सुनोगे तो शायद हमारे इस देश की काया पलटे, यह मेरी जनाब से विनती है। उस बच्चे को खड़ा किया तो मेरे दिल में बड़ी तकलीफ हुई। मैं उस वक्त एम.एल.ए. था और वहां एम.एल.ए. के पास डिस्क्रीशनरी फंड है कि वह अपने एम.एल.ए.लैड से एक गरीब को मकान दे सकता है, जो आपके एम.पी.लैड में नहीं है। आपके एम.पी.लैड में वह इण्डीविजुअल हो जाता है। मैं हैरान होता हूं। यह हमारा पॉलिसी मैटर है तो इन पॉलिसी मैटरों में हमें तब्दीली लानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा।

दूसरे, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैंने देखा है, जमीन, खेत-खलिहान पानी को तरस गये और मैडम, हमारा कंडी का एरिया है, वहां कम से कम पहले बुजुर्गों ने 1-2 हजार तालाब 1-2 हजार गांवों में बनाकर रखे हैं, जो तालाब हैं, वे जमाना बदला...(व्यवधान)

सभापति महोदया: आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी है, अब आप समापन करिये।

चौधरी लाल सिंह : जमाना बदला और उन तालाबों की शक्लो-सूरत बदल गई। वहां पर तालाब सूख गये और इन्होंने ट्यूबवैल्स का सिलसिला चलाया, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, इससे लोगों का डवलपमेंट रुक गया और पानी एक मसला बन गया। ये जो तालाब हैं, ये बर्बाद हो गये। मेरी रिक्वैस्ट है कि प्लानिंग में यह आना चाहिए कि वे हजार के हजार तालाब पानी से कैसे भर सकते हैं, कैसे उन तालाबों को वापस पानी से भरा जा सकता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया: प्लीज़, सही में जिनके यहां डैजर्ट है, उनको बोलने दें और जल्दी समापन करें। आपके सब पाइंट्स अब आ गये हैं।

चौधरी लाल सिंह : लास्ट में मेरी जनाब से विनती ह कि जब भी कभी प्लानिंग की जाये, फॉर एग्जाम्पल जम्मू-कश्मीर में कहीं करनी है तो हम 6 एम.पीज़. हैं। वहां किसी में दस हैं, किसी में 20 हैं, जो भी हैं, मेरी राय है कि वे अपने उन एम.पीज़. के एरिया में कम से कम उनसे डिस्कस जरूर करें। इसमें सबसे निकम्मा काम है कि जो बन्दा कुछ नहीं जानता, वह हमारा हिसाब कर रहा होता है। जब हमारा वह हिसाब-किताब हम करेंगे तो इससे यकीनन फायदा होगा। इसमें हमारी जो गलतियां हैं, उनको हमें सुधारना पड़ेगा।

बाकी मैं हरीश जी का बहुत वैलकम करता हूं कि वे यह संकल्प लाये। मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, आपने मुझे राजस्थान के एम.पी. श्री हरीश चौधरी के द्वारा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके को विशेष दर्जा देने या विशेष पैकेज देने के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

कोई एरिया रेगिस्तानी एरिया क्यों कहलाता है, वहां रेत होती है, इसलिए उसको रेगिस्तानी कहते हैं। रेत मीन्स सैंड डयूंस, टीबे, रेतीले धोरे। ...(व्यवधान) जो रेत होती है, वह गर्मी में जल्दी गर्म हो जाता है और सर्दी में जल्दी सर्द हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एक्सट्रीम हीट एण्ड एक्सट्रीम कोल्ड जब एरिया होता है तो वह रेगिस्तान कहलाता है। हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां एक्सट्रीम हीट भी हम देखते हैं, वहां टैम्परेचर कभी 49 और कभी 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है और अगर नीचे टैम्परेचर देखना हो, ठीक है कि जम्मू-कश्मीर में जाता होगा, लेकिन वहां एक अलग तरह का वातावरण है, लेकिन हमारे यहां जैसे चूरू इलाका माइनस में आता है, पिलानी माइनस में आता है, बीकानेर माइनस में आता है। वहां कई बार पाला जम जाता है। बाड़मेर और जैसलमेर में इतनी ठंड नहीं है। रेतीला इलाका होने के कारण एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड का एरिया कहने से वह रेगिस्तान कहलाता है, लेकिन उसका कवियों ने दूसरे ढंग से वर्णन किया है। हमारा वह एरिया कलरफुल भी है। उसको थोड़ा राजस्थानी में बोलना चाहता हूं मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। 'सोने री धरती जढें चांदी रौ आसमान', मतलब वह जो रेतीले टीबे दिखते हैं, वे धूप में और चन्द्रमा में सोने और चांदी जैसे लगते हैं।

"सोने री धरती जढ़े और चांदी रौ आसमान,

रंग रंगीलो, रस भरयो, म्हारो प्यारो राजस्थान।"

यह कलरफुल स्टेट है। हम कपड़े भी ऐसे पहनते हैं, जैसे मेरी पगड़ी है, यह कलरफुल है, महिलायें जो हमारे यहां कपड़े पहनती हैं, वह भी कलरफुल होते हैं, मैं भी कलरफुल हूं। ...(व्यवधान) रंगीन मिजाज नहीं कलरफुल हूं। हमारे यहां ऐसी डेजर्ट परिस्थितियां रहीं, विषम परिस्थितियां रहीं, लेकिन फिर भी जो लोग वहां रहे, जेनरेशन टू जेनरेशन जिंदा रहे एवं सभ्यता को भी जिन्दा रखा ।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब यह पाकिस्तान नहीं बना था, तब भी हम सीमावर्ती क्षेत्र के लोग कहलाते थे, थार रेगिस्तान के कारण। तब भी हमारा एरिया ईरान, ईराक की तरफ से लगता था। आज हम एकदम सीमावर्ती हैं। पाकिस्तान की सीमा की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो वह रेगिस्तानी इलाके के लोग वहाँ रहे हैं। हुक्मदेव जी सही कह रहे थे कि बीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, जो केवल बुनाई का काम करते हैं और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, लोग संतोषी हैं। वे पांच पशु पालते हैं। पांच पशुओं में एक गाय है, एक बैल है, गाय दूध पीने के लिए है और कुछ दही जमाने के लिए है, बैल खेती करने के लिए है, बकरी बच्चों को दूध पिलाने के लिए है, भेड़ जिससे ऊन वगैरह होती है, जो धंधा करने के लिए होती है और ऊंट ट्रांसपोर्टेशन के साधन के लिए है। ये जो पांच पशु हैं, इनके आधार पर हमारा रेगिस्तान में जीवन चलता है। पानी वहां कैसे लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत बात होती है, लेकिन हमारे इलाके में मकान कच्चे थे, तो उस समय आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। मकान कच्चे थे, तो उन्होंने देखा कि पानी मकान में नहीं ठहर सकता है, तो उन्होंने टांके का सिस्टम शुरू किया। खेतों में एक टांका बनाया गया और उसका कैचमेंट एरिया छोड़ा गया कि यहां हम खेती नहीं करेंगे। उसका जो पानी आया, वह टांके में भर गया, उसी पानी को हम पीने लगे। इसे विशेष दर्जा देना चाहिए, देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं कि हम बहुत संतोषी जीव हैं, हमें डिफीकल्टी में रहना आता है। अभी महताब साहब सही कह रहे थे कि हमारे यहां से बिड़ला गए, हमारे यहां से बांगड़ गए, हमारे यहां से डालमिया गए, हमारे यहां से सिंघानिया गए, बजाज गए, पोद्दार गए, पता नहीं कौन-कौन हमारे यहां से गए, जो देश के विभिन्न भागों में जाकर के उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की, क्योंकि उन्हें डेजर्ट में रहने की आदत थी, डिफीकल्टीज में रहने की आदत थी। उन्होंने अपना काम किया और अपनी जो बचत थी, उससे उस क्षेत्र का विकास किया, हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं।

हमारी आपके माध्यम से मांग यह है कि हमारा यह जो विशेष पैकेज है, उसमें कुछ राशि की मांग हरीश चौधरी जी ने की है। हमारी डिमांड है कि बहुत सी योजनाओं को आप क्लब कर दीजिए। हमारे क्षेत्र में एक बड़ा टांका दे दो, जिसमें पानी आ जाए और पांच पशु दे दो, ऊंट, भेड़, बकरी, बैल और गाय। पांच हमें पेड़ दे दो, टांके के आसपास लगाने के लिए, जिसमें बेर भी हो सकता है, मेडिसनल प्लांट के पौधे भी हो सकते हैं, जिससे चार-पांच साल में वे ग्रो हो जाएं तो उसको बेचकर हम इंकम भी कर सकते हैं, खेजडी भी हो सकती है। पांच हमें पौधे दे दो और पांच हमें लाइट के प्वाइंट दे दो, कैसे दे सकते हो, वह हमारे ही संसाधन हैं, विंड एनर्जी हमारे पास है, सोलर एनर्जी हमारे पास है, लेकिन टैक्नॉलाजी का उपयोग हम नहीं जानते हैं। इसमें भारत सरकार को इन्टरवेंशन करना पड़ेगा। हमारे घर में लाइट के पांच प्वाइंट दे दो, जिनसे पंखा चले, फ्रिज चले, ऐसे हमें पांच प्वाइंट दे दो। हम कारीगर लोग हैं, हमारे यहां लोग हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत अच्छा जानते हैं। आपने देखी होगी बाड़मेर की चद्दर जैसलमेर की साड़ी, बीकानेर का पट्टू, बाड़मेर का पट्टू, बीकानेर का शॉल, नापासर एक जगह है, जहां का शॉल इतना फेमस है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी उस समय मंगाया करते थे। हम इस तरह के कारीगर लोग हैं। पांच तरह के जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उसे डेवलप करने के लिए कोई धन दे दो, कोई एक काउंसिल बनाकर उसमें धन दे दो।

पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत एडवांस हैं। हमारे यहां पर फोर्ट हैं, हमारे यहां पर, जैसे मैं बीकानेर से आता हूं, हमारे यहां एक हजार हवेलियां हैं, किस तरह से लोगों ने उस समय दुलमेरा पत्थर की हवेलियां बनायी होंगी। वे हवेलियां देखने लायक हैं और लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए हमें किसी तरह के पांच इन्टरवेंशन दे दो। हमें रोड, रेल और मोबाइल टॉवर देकर कनेक्टिविटी से जोड़ दो, फिर हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी योजनाएं चाहे आप बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए, हम बहुत आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमें कठिनाई में रहना आता है। हमारे लोग संतोषी हैं, लेकिन उन्हें इतनी चीजें तो चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्यों स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं? हमारी साक्षरता की दर कम है। अभी बाड़मेर के बारे में बता रहे थे कि वहां डेढ़ परसेंट साक्षरता दर घट गयी। मैं बीकानेर से आता हूं, महिलाओं की साक्षरता दर और भी कम है। हमारे यहां पर जो मेडिकल की सुविधायें हैं, एएनएम सेंटर, पीएचसी, सीएचसी ये बहुत दूर-दूर हैं। हम 30 किलोमीटर जायेंगे तो कोई गांव नहीं आयेगा। अगर किसी महिला की डिलिवरी होने वाली हो तो वह जननी सुरक्षा योजना का लाभ कैसे ले पायेगी? हम चाहते हैं कि ऐसा इन्टरवेंशन करके जो हमारे एएनएम सेंटर्स हैं, पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, उन्हें स्ट्रेंथेन कर दीजिये। उसमें डाक्टर और नर्सेज की संख्या बढ़ा दीजिए। हमारे यहां माइन्स बहुत हैं। हमारे यहां से ही मारबल आया जिससे ताजमहल बना। हम जिस पार्लियमेंट में बैठे हैं किसी को पता नहीं है कि यह लाल पत्थर कहां से आया है। हमारे यहां से ही लाल पत्थर आया जिससे लाल किला बना। वह कितना सुंदर लगता है। महताब साहब ठीक जिक्र कर रहे थे कि जिप्सम, लाइम स्टोन हमारे पास है। वहां सीमेंट की बड़ी इकाई लग सकती है। हुकुमदेव जी ठीक कह रहे थे, राममनोहर लोहिया ने दर्शन दिया की डेजर्ट एरिया में

फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकती हैं? अभी आप का एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमी जोन) का कन्सेप्ट आया। हमारे क्षेत्र में क्यों नही जाते हैं? आप एसईजेड यहां लेंगे, उसके लिए डबल क्रॉप एरिया की जमीन लेंगे, जमीन हमारे यहां से ले लिजिए। हमारे यहां जमीन की कोई कमी नहीं है। आप विशेष दर्जा से कनेक्टिविटी दे दीजिए। लाइम स्टोन इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि बहुत बढ़िया सीमेंट बन सकती है। जैसलमेर का यलो स्टोन बहुत दूर-दूर तक एक्सपोर्ट होता है। हमारे पास ग्रेनाइट है। लक्खा की ग्रेनाइट बहुत फेमस है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां मिनरल्स की भी कोई कमी नहीं है लेकिन हम प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशान होते हैं। बाकी चीजें जो कही गई हैं उन्हें मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक या दो एसईजेड हमारे रेगिस्तान में लगे। हमारे यहां इरिगैशन फैसिलिटी बढ़े। अभी महाराजा गंगा सिंह जी का जिक्र आया। गंगा सिंह जी बीकानेर के महाराजा थे और उन्होंने वर्ष 1927 में गंग नहर का निर्माण कराया। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस नहर का अभी विस्तार हुआ जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। यह उस जमाने में आई थी। हमारे यहां पर इरिगैशन की फैसिलिटी बढ़े। आज गंगानगर और हनुमानगढ़ जहां जो चावल और कॉटन इसी नहर के कारण पैदा करता है। नहर नहीं होती तो कुछ नहीं होता। इसलिए इरिगैशन फैसिलिटी हमारे यहां पर बढ़नी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एक नेशनल डेजर्ट डेवलपमेंट ऑथरिटी भी दें। हर जगह कोई न कोई ऑथरिटी है। हमारे यहां डेजर्ट है तो उसके विकास के लिए एक डेजर्ट डेवलपमेंट ऑथरिटी भी बननी चाहिए। मैं बीकानेर से आता हूं। वहां ऊन बहुत होती है। हुकूमदेव जी वहां गए होंगे। वहां भेड़े ज्यादा हैं। ऊन अनुसंधान केन्द्र हमारे यहां है लेकिन वूलेन डौमिनेटेड मल्टी सेक्टर टैक्सटाइल पार्क बनेगा तो वह कहीं और चला जाएगा। हमारे यहां यह त्रासदी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, में कॉटन होती है लेकिन कॉटन टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो वह कोई और ले जाएगा। वह कॉटन ग्रोइंग एरिया में नहीं जाएगा। हमारे यहां ऊन होती है लेकिन पार्क कहीं और बनेगा। इस तरह सरकार का जो इन्टरवेन्शन है वह डेजर्ड मे हो तो वहां का विकास हो सकता है।

अगले दो बिन्दू मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां फेमीन कोड है। हमारे यहां पिछले साठ सालों में छयालिस बार अकाल पड़ा है। इसको हम बंजर जमीन कहते हैं। वहां पर जब अकाल पड़ता है तो एक फेमीन कोड जो हमारे यहां रेगुलेशन होता है। वह फेमीन कोड अंग्रेजों के जमाने में बना दिया गया था उसकी मजदूरी भी कम उसके रेगुलेशन भी कम, उसके मेट की पावर भी ज्यादा, आप फेमीन कोड को तो अमेंड कर सकते हैं। इसमें तो ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। इसको तो आप अमेंड कर सकते हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पशुधन बकरी पालन में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है लेकिन पशुधन से जो चीज बनती है उस पर इनकम टैक्स है। मैंने कई इन्वेस्टर से बात की कि आप हमारे राजस्थान में आकर इंवेस्ट क्यों नहीं करते हैं? वह कह रहे हैं कि पशुधन तो आप के पास है लेकिन अगर हम हड्डी पीसने की मशीन लगाएंगे तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। यह छूट तो आप दे सकते हैं। यह तो आपके हाथ में है। अगर आप डेजर्ट में इनकम टैक्स की छूट देंगे तो वहां विकास होगा।...(<u>व्यवधान</u>) रीजनल इम्बैलेंस दूर नहीं होने के कारण ही विशेष दर्जे की मांग आई। हम कोई कमजोर रहे हों ऐसा नहीं है। भक्त मीरा बाई पूरे देश में नहीं बल्कि संसार में प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप वीरता में देश में नहीं बल्कि संसार में प्रसिद्ध हैं और मैं यह कह रहा हूं कि हमारे यहां जो चीजे हुई हैं जैसे हमारे रेगिस्तान में रोहिड़ा पेड़ होता है उसके फूल इतने सुंदर होते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते लेकिन कोई टैप करने वाला नहीं है। गोडाउन पक्षी के बारे में बहुत चर्चा हुई कि वह लूप्त हो रहे हैं उनकी रक्षा कौन करेगा। कुर्जा बर्ड साइबेरिया से हमारे यहां पर आती है। रेगिस्तान का आदमी दिन ढलते ही सो जाता है। वह ज्यादा टाइम नहीं लगाता। दिल्ली या मुम्बई में आदमी रात को 11-12 बजे तक नहीं सोता, लेकिन हमारे यहां का आदमी 6-7 बजे सो जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है और प्रकृति के साथ जीता है। वह कुर्जा को देखेगा। कुर्जा कहां से आ रही है? वह साइबेरिया से हमारे यहां पानी पीने के लिए आती है। जब वहां बर्फ पड़ती है तो वह हमारे यहां आ जाती है। हमारे यहां के लोगों ने तालाब बनाए, उसे रहने के लिए स्थान दिया और दाना डालने की जगह दी। हमने सांप को भी पाला। आप देखेंगे कि सांप को कैसे पाल दिया। नमोनारान मीणा साहब बैठे हुए हैं। मैं बाड़मेर में एडीएम (डैवलपमैंट) था। मैं एक गांव में गया। मेरी नाइट स्टे एक झुम्पे में हो गई। रात को मुझे लगा कि झुम्पे में क्या हो रहा है। मैंने पूछा, क्या चक्कर है। वहां लाइट नहीं है। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा कि चिड़िया दिख रही है। वह लालटेन लाया और देखा। मैंने पूछा कि क्या यह सांप है? घरवालों ने कहा कि क्यों डरते हैं। सांप और हम साथ ही रहते हैं। सांप ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं और सांप कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अलग-अलग तरह के लोग उस क्षेत्र में हुए हैं। हमारे यहां एक पीवणा सांप होता था। हम वहां बहुत मुश्किल से जिए हैं। वह आक्सीजन पीता था। वह शायद बाबा रामदेव की तरह प्राणायाम करने वाला सांप होता था। जैसे किसी आदमी के ऊपर वह चढ़ा, आक्सीजन लिया और जैसे ही उसे लगा कि मैंने इसे काफी पी लिया, तो पूंछ मारकर चला जाता था। हम ऐसे क्षेत्र के हैं। वह उसे जगा जाता था कि अब तू मरने वाला है। वह आक्सीजन पीता था इसलिए मरता नहीं था। जलाना लाना पड़ता था। अगर किसी आदमी ने देख लिया कि पीवणा सांप जा रहा है, प्राणायाम की ताकत है या पता नहीं क्या है, वह सांप जमीन को चीर देता था और अंदर चला जाता था, बिल नहीं बनाता था। वह भी खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे यहां ऐसे जीव-जन्तु भी रहें। गोडावन पक्षी भी रहें, सब रहें। प्रकृति ने जगह सिर्फ आदमी के लिए नहीं दी, जितने भी जीव-जन्तु हैं, वे सब रहने चाहिए और हमारे यहां हर तरह के जीव-जन्तु फ्लोरा और फोना हैं। उनकी रक्षा के लिए स्पैशल पैकेज में प्रावधान होना चाहिए।

आपकी एक योजना बीएडी (बार्डर एरिया डैवलपमैंट) है जिसके कारण बार्डर एरिया का डैवलपमैंट करते हैं। मैं इसमें एक अमैंडमैंट चाहता हूं कि अगर सीमा क्षेत्र में कोई नगरपालिका आ गई तो कहते हैं कि नगरपालिका क्षेत्र में हम नहीं देंगे। वह पांच किलोमीटर के अंदर ही है। मैं आपके माध्यम से ये छोटे-छोटे अमैंडमैंट्स सरकार को सुझाना चाहता हूं। अगर इस तरह के अमैंडमैंट्स होंगे तो रेगिस्तान एरिया जिसमें राजस्थान के वैस्टर्न पार्ट के 16 जिले आते हैं, हम राजस्थान को हरा-भरा कर सकते हैं। जैसे आपने पहाड़ी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के लिए टैक्स हॉलिडे घोषित किए, इनकम टैक्स की छूट दी, एक्साइज की छूट दी, वैसी छूट पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी दीजिए तो हम राजस्थान का विकास कर सकते हैं।

श्री हरीश चौधरी प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से जो संकल्प लाए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदया, श्री हरीश चौधरी ने गैर-सरकारी संकल्प द्वारा जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने 26 अगस्त, 2011 को इस प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया था। उसके बाद आज इस पर दूसरी बार चर्चा हो रही है। रेगिस्तान में जो जन-जीवन है, पशु जीवन है, उन्होंने उनकी व्यथा और पीड़ा के बारे में उल्लेख करते हुए विकास की बात की। उनकी मांग, बात, अनुरोध बिल्कुल जायज है। राष्ट्र के सामयिक विकास के संदर्भ में उनका प्रस्ताव सामयिक ही नहीं बल्कि इस मामले में प्रासंगिक है। संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और सरकार का प्रयास योजना के माध्यम से होगा कि क्षेत्र में संतुलित विकास हो और आर्थिक असंतुलन, विकास का असंतुलन दूर हो।

श्री चौधरी जी ने दो बातें कही हैं। श्री भृतहरि मेहताब जी ने भी चर्चा की है कि वहां के रहने वाले लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के मामले में कि विद्यालय, यातायात हो और जो ग्रामीण कुटीर उद्योग-धंधे हैं, उन्हें बाजार मिले, मार्केट कनेक्टिविटी हो,

रोजगार सृजन के लिए पूंजी हो और शैक्षणिक स्तर से उनका जीवन कैसे उठे, उस पर जोर दिया जाये। उन्होंने अपने भाषण में दो बातें कही थीं कि इस देश में एक कोल्ड डेजर्ट है और एक हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट के विकास की बात की गयी है, प्रयास भी किया गया है लेकिन जो हॉट डेजर्ट है, उसका जन-जीवन तपता रहता है और वे लोग कैसे रहते हैं, इस मामले में अब तक सरकार ने कोई आंकलन नहीं किया।

अभी श्री अर्जुन मेघवाल जी ने कहा कि एक डेवलपमैंट अथॉरिटी बनी। वह राज्य सरकार के क्षेत्राधीन है। यह अथॉरिटी राज्य सरकार बनायेगी, लेकिन राज्य सरकार बनायेगी, तो पैसे का सवाल उठता है। सारा मामला पैसे पर चला आता है कि पैसे कहां हैं? स्वयं हरीश चौधरी जी ने दो बातें का उल्लेख किया था कि हमारा जो नार्थ ईस्ट प्रदेश है, उसके विकास और उसे राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया और उसे बनाकर विकास को गति दी गयी। फिर सरकार ने सैक्टोरल एप्रोच किया कि किस-किस सैक्टर में ज्यादा जोर दिया जाये, ताकि सैक्टोरल डेवलपमैंट हो और राष्ट्र की मुख्य धारा में नार्थ ईस्ट प्रदेश कैसे जुड़ें। उसी आधार पर उन्होंने कहा कि मरुस्थल के विकास के मामले में भी सरकार को विचार करना चाहिए। यह ठीक है कि यहां प्लानिंग मिनिस्टर बैठे हैं। यह प्लानिंग का मामला है, लेकिन अलग मंत्रालय नहीं खुल सकता, तो कम से कम जो जनजातीय मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अधीन मरुस्थल के मामले को देखने के लिए एक कोषांग, एक विभाग खोला जा सकता है। उस विभाग को खोलकर सरकार उसे देख सकती है।

अभी अर्जुन मेघवाल जी ने राजस्थान के बारे में बहुत चर्चा की है। यह ठीक है कि हमारे देश की परम्परा के साथ राजस्थान की परम्परा एक महत्व पैदा करती है, एक सुगंध पैदा करती है। राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो हम भी गौरवान्वित होते हैं। राजस्थान की वीरांगनाओं से लेकर मीरा तक की आपने चर्चा की है, तो हम भी बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन उसी राजस्थान में पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छे-अच्छे स्थान हैं। राजस्थान के लिए पर्यटन एक उद्योग है, तो राजस्थान में रेगिस्तान भी है, जिसे जैसलमेर कहते हैं। वर्ष 1988 में जब बिहार विधान मंडल की कमेटी जैसलमेर गयी थी, तो मैं भी कमेटी के साथ गया था। हमने देखा कि जैसलमेर के जनजीवन में सबसे बड़ा संकट जल का है। लोगों ने स्नान करने से लेकर पीने के पानी तक की अपनी पीड़ा बतायी। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कर्मचारी वहां से आया। उसने हमसे कहा कि हम जैसलमेर से आना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप वहां से क्यों आना चाहते हो, तो उसने कहा कि वहां जल की सबसे बड़ी दिक्कत है। वहां स्नान से लेकर पीने के पानी तक बहुत दिक्कत होती है। आज भी जैसलमेर में पानी बाहर से टैंकर में आता है। इसलिए जैसलमेर रेगिस्तान का सबसे बड़ा पार्ट है। हम लोगों ने कहा कि हम रेगिस्तान का इलाका देखने के लिए जायेंगे, तो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गयी और एक सीमा तक जाकर हमें रोक दिया गया कि इसके बाद हम नहीं जा सकते। वहां के स्थानीय लोगों से जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई जीवन नहीं है। हमने सोचा था कि आजादी के बाद हमारे बारे में सरकार सोचेगी। सरकार हमारा जीवन भी राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ेगी। लेकिन हमारे यहां पहुंचना मुश्किल है और जब आप पहुंच जायेंगे तो वहां से आना मुश्किल है क्योंकि हमारे यहां हरेक चीज की समस्या है और यह समस्या आज तक विद्यमान है। हरीश चौधरी जी ने अपने भाषण में वहां की व्यथा, पीड़ा व्यक्त की है कि आज भी वह समस्या, चाहे जल, यातायात, टेलीफोन, विद्यालय, शिक्षण, पठन-पाठन, चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ये सारी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, जो हमने वर्ष 1988 में देखी थीं। हमने लोगों से पूछा कि क्या अब भी वही जीवन है, तो लोगों ने कहा कि अब भी वही कष्टमय जीवन है। भोग रहे हैं लोग वहां, जीवन को जी नहीं रहे हैं। राजस्थान में मरूस्थल में लोग कष्टमय जीवन को झेल रहे हैं, जीवन को जी नहीं रहे हैं। यह ठीक है कि विलेज आर्टिजन, ग्रामीण कुटीर उद्योग-धंधों को आप विकसित कीजिए, लेकिन आधुनिक भारत में, आधुनिक युग में, वैश्वीकरण में रोजगार सृजन के जो तरीके हुए हैं, उनको भी वहां ले जाना चाहिए और इसके लिए सिर्फ राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या अन्य किसी दल की सरकार हो, उसके पास इतने संसाधन नहीं हैं। आप वहां से नेचुरल गैस निकालते हैं, आप पोखरण के बारे में बता रहे हैं कि पोखरण वहीं है। आप वहां से पेट्रोलियम निकालते हैं, लेकिन वहां की रायल्टी से रेगिस्तान का कैसे चहुंमुखी विकास हो, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। सरकार की तरफ से माननीय श्री अश्विनी कुमार, प्लानिंग मिनिस्टर यहां बैठे हैं, वह इस बात का जवाब दें कि आपने पूर्वोत्तर प्रदेशों के लिए योजना बनाई है, मंत्रालय बनाया है और कूमांकित किया है बजटीय उपबंध बजट में। अच्छी बात है, आपने अच्छा किया है। लेकिन उसी तर्ज पर जो रेगिस्तान है, मरूस्थल है, जो हॉट डेजर्ट है, उसके लिए भी करना चाहिए। रेगिस्तान का वह इलाका देश के भूभाग से कटा हुआ है। उसका कैसे सम्यक विकास हो, वह राÂट्र की मुख्यधारा से कैसे जुड़े। अगर आप इसके लिए अलग मंत्रालय नहीं बना सकते हैं, तो जनजातीय मंत्रालय में या योजना मंत्रालय में इसके लिए विभाग बनाना चाहिए।

इसी बात के साथ, मैं हरीश चौधरी जी के इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I would like to support the Resolution moved by our esteemed colleague Shri Harish Choudhary in regard to special economic development package for the desert regions of the country. Not only that, he also sought that the package should be at par with the North-Eastern States to mitigate the problems being faced by the people living in the deserts.

In India the total area of deserts is 2,08,110 square kilometers and it spreads over four States namely, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. The desert area has been divided as Great Desert and Little Desert. Great Desert forms a part of Thar Desert which extends from Pakistan in the West from the edge of Rann of Kutch beyond the Luni River. And the Little Desert extends from the Luni between Jaisalmer and Jodhpur up to Northern West. The arid zone in India occupies 12 per cent of the total land. Further, there are 70,000 square kilometres of cold deserts in Ladakh and Himalayas together.

A number of Members have already spelt out the problems of the people of desert areas. As far as Thar desert is concerned, Thar desert is the most populous desert in the world. It is a living and dynamic desert. A square kilometre area of Thar is occupied by 37 persons. In contrast, in other parts of the world only seven persons occupy a square kilometre of desert area. Not only that, it is a land which is recognised as a land of biodiversity.

The uniqueness of the desert is that we experience high temperature, low precipitation and high rate of evaporation. I would like to draw the attention of the entire House to the fact that it is very alarming to note that desertification has been going on continuously, and it is encroaching upon the fertile lands of our country. It needs to be stopped first. So, we need to have a comprehensive strategy to impede the expansion of desert area so that we can save our fertile land. The desert is spreading outwards at the rate of half-a-kilometre per year. Could you imagine that it is encroaching at the rate of approximately 130 square kilometre of fertile land every year? May I know from the hon. Minister whether any study has been done to ascertain the area of desertification and whether the Government has taken any steps in consultation with the other world organizations, to stem the expanse of desert? As we are all aware, we had the Rio Convention. It is a planning workshop, carried out in 1999, within the framework of regional cooperation to combat desertification in the Middle East by utilizing a participatory approach. May I know whether our Government is taking any steps by participating in those approaches and in those conventions?

Our desert is being taken care of by various schemes. Earlier we had desert development programme in 1977-78. Now all the programmes have been subsumed under the Integrated Watershed Management Programme from 2009. Under Integrated Watershed Management Programme, the identified areas of desert development have been given due priority, while selecting the projects for implementation. May I know from the hon. Minister how many projects were sanctioned under Desert Development Programme, how much money has been allocated for that purpose, whether the target in this regard has been achieved and whether it is a fact that the money has not been spent fully so far?

The problem especially in the desert is that there is soil erosion which needs to be tackled. Soil erosion is a serious problem in the desert. The chief agent for soil erosion is blowing of wind, especially the South-Western wind. Sometimes, it accelerates the velocity to 140 kilometres per hour. The wind of that velocity simply evaporates the moisture that remains in the soil. Not only that, it also physically removes soil from one place to another. The Government should contemplate measures to protect land from soil erosion by wind.

Soil conservation is another important aspect if we really wish to help the people of desert regions. Only if we are able to conserve the soil, it will have the requisite moisture which will help in vegetation and which in turn will serve other purposes.

As Shri Meghwal mentioned, in desert region animal husbandry is recognised as a great profession. Per capita availability of animal is the highest in the desert areas than in other parts of the country. But the fact is, due to over-grazing and also trampling by cattle and other animals the land is being further degraded. The Government should take rational scientific measures so as to save on the one hand the livestock and on the other hand to take care of the conservation of soil. In this regard I would like to offer some suggestions.

In the canal-irrigated areas the Government should adopt mixed farming. This would maintain high-yielding dairy cattle and cultivation.

Artificial insemination should be taken up in the canal command areas and should be intensified around urban areas, in the existing milk schemes, of the States.

While grass reserves would yield a good quantity of grass, seed production should also be undertaken in properly organised seed production farms in areas with good irrigation facility.

Irrigation is an imperative need to save the people of desert region. As has been mentioned by other Members, there is enormous mineral wealth in the desert region. This mineral wealth should be conserved and utilised to give optimum results.

Market-oriented industries based on agricultural products, livestock and minerals should be developed in all the large, medium and small scale sectors.

An efficient transport network should be developed in the region which should interlink urban centres as well as villages.

Areas of scenic beauty should be developed conserving the important existing features such as sand dunes to the west of Jaisalmer.

Recreational areas should be developed by utilising the existing features and by further developing the same tourism should be promoted. Tourism is a smokeless industry which can easily be flourished in the desert region.

I would also like to mention that along with proper land use activities, a considerable area should also be kept for afforestation. I would like to put emphasis on afforestation. Afforestation should be made to check further expansion of the desert and attract more rainfall in the desert region. We have to do well in afforestation for the development of desert region. It should be given high priority along with conservation of soil and prevention of soil erosion by wind. These are the suggestions that I would like to make.

Last but not least, North-Eastern Region is an amalgamation of seven States but only a few areas of the States are called desert areas. However, I would support this Resolution and draw the attention of the concerned Minister to take necessary action.

*m1

*__SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR)__ : Hon. Madam Chairperson, I stand to support resolution introduced by Shri Harish Chaudhary. Anantpur district of Andhra Pradesh is showing indications of turning into a desert. Scientists also expressed similar fears. In such a scenario, it is our responsibility to save these districts. In our country, Anantpur district is next to Jaisalmer district of Rajasthan where lowest rainfall is recorded. We should note that even after digging large number of bore wells in these villages, drinking water is not available. I would like to bring to your notice a very serious situation, where people of this region are asking only for drinking water. Inspite of many water conservation programmes, the ground water levels could not be replenished. When there is no adequate rainfall, how the ground water levels can be replenished?

The Government report states that 14 out of 16 crops resulted in failures. In such a situation, we should understand how the people of this region survives without any means of livelihood. In Anantpur district, out of 16 crops, 14 crops resulted in failure and Central Government is offering only 3% subsidy on interest, that too for those farmers who repaid their loans on time. The farmers of Anantpur district where crop failure is rampant are not in a position to avail this subsidy. Anantpur district receives scanty rainfall and for last 30 years only groundnut is being cultivated here. Neither State Government nor Central Government is in a position to support groundnut sowing in these regions.

It incurs an expenditure of Rs.10,000 per acre of groundnut cultivation. When 14 out 16 crops failed, we should understand how the farmer of this region is living and surviving. And neither State Government nor Central Government is in a position to rescue these farmers. Recently, State Government had submitted a representation in this regard, seeking guidance on how to save this district. A central team visited this district and made some recommendations which were as good as recommendations made by Britishers. There was nothing new in those recommendations. If the Central Government does not announce special schemes to save this district, it will turn into a desert.

After agriculture, weaving is the main occupation of this district. Around 2 lakh weavers are dependent on weaving silk sarees. Weavers' welfare is also neglected by state as well as Central Governments. In 1995, a law was enacted to protect the interests of the weavers. Under that law, 11 articles were reserved to be manufactured only by handlooms and should not be manufactured on power looms or by any other means. But the Governments are not implementing this law effectively. These 11 reserved articles are being manufactured by other means and are being supplied throughout the country. The Central Government is not in a position to implement this law effectively. I plead the Government to implement that law effectively and save the weavers of this district.

Third main occupation of this district is sheep rearing. Around 20 lakh shepherds are dependent on sheep rearing. Fodder is not available for six months in a year. I request the Government to take steps to protect the interests of shepherds and save this district from turning into a desert. Special schemes should be announced for this district. With this request, I conclude.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदया, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए। आदरणीय श्री हरीश चौधरी द्वारा 26 अगस्त 2011 को पेश किये गये संकल्प को समर्थन देने के लिए जो मुझे आपने अवसर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा जो राजस्थान के बगल में है, हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा सामाजिक संबंध भी राजस्थान से है। जो राजस्थान की समस्याएं हैं, वही मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा की हैं। हमारा क्षेत्र दलित, आदिवासी लोगों का क्षेत्र है और बहुत पिछड़ा हुआ है। अरावली गिरी का जो पहाड़ी प्रदेश है, वहां से हमारे प्रदेश की शुरुआत होती है और राजस्थान जिसे वीरभूमि कहते हैं, जिस प्रदेश ने बहुत सारे योद्धा इस देश को दिये हैं, इस भूमि को मैं वंदन करता हूं और महाराणा प्रताप जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों के साथ लड़े थे, वह जब हमारे प्रदेश में साबरकांठा में जो विजय नगर है, वहां वह जंगलों में रहे थे और हमारे प्रदेश में जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था। जब मैं थोड़े दिन पहले वहां गया था तो जिस जगह पर महारानी ने हिचका लगाया था, वह जगह भी मैंने देखी और जहां वामाशाह आए थे और महाराणा प्रताप को मदद दी थी, वह स्थल मेरे प्रदेश में है। मैं अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उसके बारे में कुछ हो सके, इसके लिए निवेदन करता हूं।

हमारा जो पूरा क्षेत्र है, वह कृषि एवं पशु-पालन आधारित है। वहां उद्योगों का कोई विकास नहीं हुआ है क्योंकि रेलवे का विकास नहीं हुआ है और आप जानते हैं कि रेलवे ही विकास की धरोहर है। जहां जहां से रेल गुजरती है, वहां विकास होता है। हमारे वहां स्टोरेज भी नहीं है, इसके लिए किसान हैरान परेशान है। समय पर खाद्य न मिलने से कृषि प्रभावित हो रही है। यहां से दिल्ली, मुम्बई जाने के लिए भी कोई रेल सुविधा नहीं है। हिम्मतनकर, खेडब्रह्मा रेल लाइन को अंबाजी, आबुरोड तक बढ़ाने की योजना को योजना आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा है, मैं योजना आयोग से विनती करता हूं कि इसे स्वीकृति दी जाए।

महोदया, दूसरा बिंदु भूमि सुधार का है। यहां की भूमि कंकरीली और पत्थरी है इसलिए यहां ज्यादा अच्छी फसल पैदा नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए विशेÂा पैकेज मिले जिससे भूमि सुधार हो। यहां सिंचाई की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है।

सभापति महोदय : महेंद्र सिंह जी, जब इस विषय पर अगली बार चर्चा होगी तब आप इसे शुरु करेंगे। मुझे लगता है अब समय हो गया है। आपको चांस मिलेगा और आप इसे फिर शुरु कर सकते हैं।

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, May 7, 2012/ Vaisakha 17, 1934 (Saka).

---

* Not recorded.

* Laid on the Table.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the Speech originally delivered in Telugu.